



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2018/पौष 20, 1939

No. 18]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2018/PAUSHA 20, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

अधिसूचना

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: जापान एवं कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 14/31/2015-डीजीएडी.—जबकि अलकाली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) ने संबद्ध सामानों के चार उत्पादकों अर्थात् मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मैसर्स गुजरात अलकालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एसआईईएल (जिन्हें यहां बाद में "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) सहित कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों की ओर से जापान एवं कतर (जिन्हें यहां बाद में संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां बाद में प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

- जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में दिनांक 14 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/31/2015-डीजीएडी द्वारा अधिसूचना जारी की जिसमें पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाता है, की राशि की सिफारिश करने के लिए जापान एवं कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई थी जो कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

2. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें जापान एवं कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के पाटन का आरोप लगाया गया है।
- ii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना जारी की।
- iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांचें शुरू करने के संबंध में सूचित किया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें।
- v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना देने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:
 - i. असाही कसेई केमिकल्स कारपो.
 - ii. पेक्को लि.
 - iii. असाही ह्लास कंपनी सीमी केमिकल कं. लि.
 - iv. टोकुयामा कारपो.
 - v. कतर विनिल कंपनी लि. क्यूएससी
 - vi. सन्नोउ कं. लि.
 - vii. तोसो ऑर्गेनिक केमिकल कं. लि.
 - viii. कनेका कारपो.
- vi. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
 - i. मैसर्स असाही ग्लास कं. लि.
 - ii. मैसर्स हीरानायावरणम केमिकल्स एंड अलकालीज पीटीई लि.
 - iii. मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.
 - iv. मैसर्स तोसो कारपोरेशन
 - v. मैसर्स शिन-इत्सु केमिकल कं. लि.
 - vi. मैसर्स कतर विनिल कंपनी (क्यूवीसी)
 - vii. मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी.
 - viii. मैसर्स ट्रिकोन ओवरसीज इंक.
- vii. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी:
 - i. अभय केमिकल्स लि.
 - ii. अरविंद मिल्स लि.
 - iii. सेंट्रल पल्प मिल्स लि.
 - iv. गोजरेज सोपास लि.
 - v. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि.
 - vi. इंडियन ऑयल कारपो. लि.
 - vii. लिंक फार्मा लि.
 - viii. नर्मदा केमोच्योर पैट्रोकेमिकल्स लि.
 - ix. पैब केमिकल्स (पी) लि.

- x. रूबामिन लि.
 - xi. टोरेट गुजरात बायोटेक लि.
 - xii. बिरला सेलुलोज लि.
 - xiii. दीपक नाइट्रेट लि.
 - xiv. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि.
 - xv. इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपो. लि.
 - xvi. जेसिथ डाइकेम लि.
 - xvii. मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि.
 - xviii. निरमा लि.
 - xix. रामा न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स लि.
 - xx. सबेरो ऑर्गेनिक्स लि.
 - xxi. ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्रीज लि.
 - xxii. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि.
 - xxiii. हित्सु इंडस्ट्रीज लि.
 - xxiv. अदानी विल्मर लि.
 - xxv. श्री रामचंद्र स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लि.
 - xxvi. दौराते ऑर्गेनिक्स लि.
 - xxvii. हरीश कुमार एंड कंपनी
 - xxviii. हिंदुस्तान लीवर लि.
 - xxix. कयानीडेस एंड केमिकल्स कंपनी
 - xxx. अदानी एक्सपोर्टर्स लि.
 - xxxi. लिब्रा फोम्स
 - xxxii. बिलाग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
 - xxxiii. सीजे शाह एंड कं.
 - xxxiv. हिंदुस्तान लिंक एंड रेसिन्स लि.
 - xxxv. अलकालीज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- viii. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
- i. नालको
 - ii. वेदांता लि.
- ix. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- x. अन्य सूचना आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों से मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया गया था।
- xi. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की अनुकूलतम उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी बिक्री करने की लागत निर्धारित की गई थी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा एनआईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।
- xii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें और उसे नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

- xiii. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार, संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए 22 अगस्त, 2017 को मौखिक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों तथा विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों और हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए, को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दायर करें।
- xiv. अंतिम जांच परिणाम जारी करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर, 2017 थी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा उसे नियम 17(1)(क) के अनुसार 13 जनवरी, 2018 तक तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया।
- xv. निर्दिष्ट प्राधिकारी बदल जाने के कारण तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के एटीएमए के मामले में निर्णय के अनुसार नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 30 अक्टूबर, 2017 को दूसरी मौखिक सुनवाई की गई थी। जिन पक्षकारों ने दूसरी मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दायर करने के लिए अनुरोध किया गया था जिसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- xvi. याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दी गई सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया था। आवश्यक संशोधन के साथ इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर ही, जहां तक लागू था, वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।
- xvii. यह जांच 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर 31 मार्च, 2016 (जांच की अवधि) की अवधि के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) को शामिल किया गया है।
- xviii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच की अवधि समेत पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आकड़ों पर भरोसा किया है।
- xix. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों का इस अंतिम जांच परिणाम में समाधान कर दिया गया है।
- xx. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुँच से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच में काफी अड़चन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- xxi. एक प्रकटन विवरण 26.12.2017 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य शामिल थे जिसमें प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए 04.01.2018 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने उपयुक्त रूप से हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर विचार किया है।
- xxii. इस अंतिम जाँच परिणाम में *** चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- xxiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर= 65.91 रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग के विचार

3. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं:

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड (रासायनिक नाम NaOH) है जिसे सामान्य रूप से सभी रूपों में कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है।
- कास्टिक सोडा एक अजैविक, सोपी, सशक्त रूप से अलकालीन और गंधहीन रसायन है तथा लुग्दी एवं कागज, न्यूज प्रिंट, विस्कस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमीनियम, कॉटन, टेक्सटाइल, टॉयलेट और लोड्री साबुन, डिटर्जेंट, डाइस्टर, ड्रग और फार्मास्युटिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग आदि के विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों अर्थात् तरल एवं ठोस के रूप में तीन प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं अर्थात् मरकरी सेल प्रक्रिया, डायफ्रॉम प्रक्रिया और मेम्बरेन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इन तीन प्रक्रियाओं में अंतर से विभिन्न

अभिलक्षणों के संदर्भ में उत्पाद में अंतर नहीं होता है। द्रव रूप को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है और ठोस रूप को पुनः उत्पाद के रासायनिक गुणधर्मों में किसी परिवर्तन के बिना तथा आसानी से द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस रूप को आसानी से भंडारण कर सकते हैं और परिवहन भी कर सकते हैं जबकि द्रव रूप में आसान घुलनशीलता होती है। अंतिम प्रयोग के लिए दोनों रूपों को एक-दूसरे के स्थान पर तथा एक-दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है। आयात प्रमुख रूप से फ्लैक रूप में आयात की बहुत कम मात्रा में द्रव रूप में आयात किए जाते हैं। तथापि, दोनों रूप स्पष्ट रूप से एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं तथा समान वस्तु हैं। अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद में कास्टिक सोडा (द्रव एवं फ्लैक दोनों) के सभी रूपों को शामिल किया है।

- iii. कास्टिक सोडा सीमा शुल्क शीर्ष 2815.11 एवं 2815.12 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। आईटीसी आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार यह उत्पाद सीमा शुल्क शीर्ष 2815.1110, 2815.1120 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा वर्तमान जांच के क्षेत्र में किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
- iv. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा और संबद्ध देश से आयातित कास्टिक सोडा भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पादन विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं में तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से आयातित कास्टिक सोडा के समान वस्तु मानी जानी चाहिए।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक तथा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तुओं के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

5. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों में काफी अंतर नहीं है। यहां तक कि यदि उत्पाद विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाए तो भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे मानदंडों के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु के रूप में मानी जा रहे हैं।

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र तथा आधार

घरेलू उद्योग के विचार

6. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति जांच की शुरुआत की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गई है कि वर्तमान याचिका एएमएआई द्वारा संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादकों की ओर से दायर की गई है। संबद्ध सामानों के चार प्रमुख उत्पादकों अर्थात् मैसर्स गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसईआईएल ने विश्लेषण के लिए आवश्यक लागत एवं वित्तीय सूचना प्रस्तुत की है।
 - ii. किसी भी भागीदार (याचिकाकर्ता) कंपनी ने उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही कोई संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक/उत्पादक से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन में भारतीय उत्पादन

में प्रमुख अनुपात है। अतः प्रतिभागी कंपनियों ने आधार की आवश्यकता को पूरा किया है तथा पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से वे घरेलू उद्योग हैं।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

7. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. घरेलू उद्योग के वास्तविक आधार तथा संगठन के संबंध में स्पष्टता का कुछ अभाव प्रतीत होता है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि याचिका उत्पादकों की ओर से एएमएआई द्वारा दायर की गई थी, तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन सी कंपनियों की वर्तमान में क्षति एवं घरेलू उद्योग के मानदंडों के संबंध में जांच की जा रही है। किसी अद्यतन सूचना के अभाव में यह माना जाता है कि याचिका दायर करने के समय से घरेलू उद्योग के भागीदारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा इसीलिए घरेलू उद्योग में जीएसीएल, डीसीडब्ल्यू, ग्रासिम और एसएआईएल हैं।
 - ii. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के आयात में लगे हैं। जैसा कि जीएसीएल की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने लगभग *** मी. टन कास्टिक सोडा द्रव का आयात किया और 2015-16 (जांच की अवधि) की अवधि के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को उसी का व्यापार किया।
 - iii. यह तथ्य कि 34 उत्पादकों में से केवल 10 उत्पादक याचिका का समर्थन कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि शेष उद्योग जापान से आयात को खतरे के रूप में नहीं देखते हैं और ये उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन एवं खपत में अपना कुल हिस्सा बढ़ाने में सक्षम रहे हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. जांच के लिए आवेदन अलकालीज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर किया गया था। आरंभिक तौर पर संबद्ध सामानों के चार उत्पादकों अर्थात् मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मैसर्स गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसआईएल, जिनका संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादन का लगभग 47.70 प्रतिशत पर नियंत्रण था, ने जापान एवं कतर से तथाकथित पाटन के विरुद्ध क्षति संबंधी जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उत्पादकों के रूप में भाग लिया।
9. याचिकाकर्ता कंपनियों ने घोषित किया है कि वे न तो संबद्ध देश में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित हैं और न ही विचाराधीन उत्पाद के भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबंधित हैं।
10. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि एक याचिकाकर्ता कंपनी मैसर्स जीएसीएल, जिन्होंने जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात किया है, को नियम 2(ख) के अनुसार अपात्र माना जाना चाहिए। तथ्यों की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि चीन जन गण एवं ईरान से अपर्याप्त मात्रा में आयात किए गए थे जो संबद्ध देश नहीं हैं। इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जीएसीएल को एक पात्र घरेलू उत्पादक मानना उपयुक्त समझा जाता है।
11. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि 34 उत्पादकों में से केवल 10 उत्पादकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका एएमएआई द्वारा दायर की गई है जो कि एक एसोसिएशन है और जो सभी 34 घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व कर रही है जिनमें से 10 उत्पादकों ने आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है तथा आंकड़े प्रदान किए हैं। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अन्य उत्पादक आवेदन का विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है।
12. इस मामले के कानूनी प्रावधानों और तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक दोनों संबद्ध देशों अर्थात् जापान और कतर के लिए नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं। आवेदक के उत्पादन का समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है तथा यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

घ. विविध मुद्दे

घरेलू उद्योग का विचार

13. घरेलू उद्योग के अनुरोध सारभूत रूप से निम्नलिखित हैं:
 - i. हितबद्ध पक्षकारों ने जापान के विरुद्ध याचिका वापस लेने के संबंध में अपनी स्थिति बदल दी है, उन्होंने वह मुद्दा उठाया है जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है और इसीलिए जापान के विरुद्ध याचिका को वापस लिया। जहां तक निर्णायक समीक्षा जांच का संबंध है, वह मुद्दा वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर है।
 - ii. जापान के विरुद्ध आवेदन की वापसी से कतर के संबंध में याचिका की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र में जापान एवं कतर के संबंध में अलग-अलग सूचना थी। एक संबद्ध देश के विरुद्ध जांच को रद्द करने से जांच की शुरुआत अवैध नहीं हो सकती। जांच की शुरुआत के समय तथा अंतिम जांच परिणाम के चरण पर प्राधिकारी के समक्ष तथ्य बदल

सकते हैं। किसी भी पक्षकार को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को दोनों देशों की सूचना अलग-अलग दी गई है और उनके पास खुद कतर के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त समय है। कुछ जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी कुछ आयातों को अपाटित मान सकते हैं तथा उसे क्षति विश्लेषण के लिए अलग कर सकते हैं। तथापि, उससे जांच की शुरुआत अथवा जांच अथवा निर्धारण रद्द नहीं हो जाता।

- iii. न ही घरेलू उद्योग और न ही हितबद्ध पक्षकारों को प्रस्तावित निरस्तीकरण के संबंध में उनके विचार देने के लिए अवसर दिया गया और न ही वापसी को रद्द करने का निर्णय नियमों के अनुरूप है। यह पूर्णतया अस्पष्ट है कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किए बिना और याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना अनुरोध/आवेदन को रद्द अथवा स्वीकार कर सकते हैं।
- iv. नियम 14 में "ग" तथा "तत्काल ही" शब्द का प्रयोग किया गया है, उपर्युक्त नियम में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योग याचिका को वापस ले सकता है। वस्तुतः याचिकाएं यूरोप में प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद नेमी रूप से वापस की जाती हैं। इसी प्रकार, अमेरिकी कानून में यह प्रावधान है कि समीक्षा अनुरोध याचिकाकर्ता द्वारा तभी वापस लिया जा सकता है जब निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर दिया हो। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि मौखिक साक्ष्य के बाद याचिका की वापसी विलंब के स्तर पर है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आयोजित मौखिक सुनवाई विलंब से हुई है।
- v. संबद्ध सामानों का पाटन करने वाले बहुत से देश वैश्विक मांग आपूर्ति के अंतराल के कारण है और वस्तुतः यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति पाटन के लिए सुभेद्य है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता को अपने तर्कों को तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए, न कि अटकलबाजी पर। इसमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता थी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं तथा यह मानते हुए भी कि पाटित आयातों को छोड़कर ऐसे अन्य कारक भी हैं, यह दर्शाया जाना चाहिए कि कारक ऐसा है जो संबद्ध देश से पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को तोड़ता है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच के संबंध में कई मुद्दे उठाए हैं जिनमें घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में अपनाए गए पाटन निर्धारण के सिद्धांत और उनके क्षति दावे शामिल हैं। यद्यपि पाटन एवं क्षति निर्धारण से संबंधित मुद्दे इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर ले लिए गए हैं, तथापि, जांच में पक्षकारों द्वारा उठाए गए सामान्य मुद्दों की संगत सीमा तक निम्नलिखित रूप में जांच की गई है। संक्षिप्तता की दृष्टि से पक्षकारों के अनुरोध और उनमें उठाए गए मुद्दे सारभूत रूप से निम्नलिखित रूप में हैं:
 - i. कुछ निर्यातकों ने मांग की कि जापान के विरुद्ध वर्तमान जांच रद्द की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के अनुसार जापान से आयातों के संबंध में अपने दिनांक 24 अगस्त, 2017 के पत्र द्वारा अपना आवेदन वापस ले लिया है।
 - ii. कुछ निर्यातकों ने यह उल्लेख किया है कि आवेदन की वापसी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह कि वापसी इसलिए की गई है क्योंकि घरेलू उद्योग को नकारात्मक पाटन एवं नकारात्मक क्षति का डर है।
 - iii. इसके अतिरिक्त, जापान के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर तथा इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के आयातों के विरुद्ध एमटीआर जांच में प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से पूर्व जांच में शुल्क की "शून्य" दर लेने वाले देश के रूप में जापान को अलग करना नोट किया था, जापान से कास्टिक सोडा के आयात के संबंध में नए सिरे से पाटनरोधी जांच शुरू की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग तथा प्राधिकारी का यह मत था कि जापान के संबंध में कोई मौजूदा शुल्क नहीं है, विरोध का कोई स्तर अब जापान के विरुद्ध समीक्षा जांच शुरू कर नहीं लिया जा सकता।
 - iv. डीसीडब्ल्यू ने अपना आवेदन वापस ले लिया है तथा कतर से आयातों पर वर्तमान जांच का अपने दिनांक 14 दिसंबर, 2016 के पत्र द्वारा समर्थन किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि घरेलू उत्पादकों में कोई परिवर्तन हुआ है जो कि याचिका का समर्थन करते हैं, तो प्रपत्र-IV क और प्रपत्र-IV ख में नए आंकड़े दिए जाने चाहिए। चूंकि घरेलू उद्योग के संगठन में परिवर्तन से पूरे क्षति विश्लेषण में संभावित रूप से परिवर्तन आ सकता है, अतः इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन में उनके हितों की रक्षा के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देने के लिए नए सिरे से सुनवाई होनी चाहिए।
 - v. याचिकाकर्ताओं ने अमेरिकी डॉलर में पहुँच मूल्य भी शामिल किया है जो कि स्पष्ट रूप से वह मुद्रा नहीं है जिसमें कि कोई भी भारतीय क्रेता प्रचालन करता हो, इसे कीमत में कमी दर्शाने के लिए किया गया है।
 - vi. याचिकाकर्ता पर्याप्त सूचना देने में विफल रहे हैं अथवा उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयात, कीमत कटौती तथा क्षति संबंधी आंकड़ों के संबंध में अनुचित सूचना एवं आंकड़े प्रदान किए हैं।
 - vii. जापान को जांच के क्षेत्र से हटाने से पूरी जांच निष्फल हो गई है क्योंकि जांच की शुरुआत के समय कतर के लिए किया गया स्वतंत्र मूल्यांकन कभी नहीं था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

15. विभिन्न अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

i. नियमावली 1995 के नियम 14क में यह उल्लेख है कि:

जांच का निरस्तीकरण: निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल ही जांच को रद्द करेंगे, यदि –

(क) उसे उस प्रभावित घरेलू उद्योग से या उनकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में प्राप्त हो जिनके कहने पर जांच शुरू की गई थी;

ii. यहां नियम को सामान्य रूप से पढ़ने पर यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग समग्र रूप से जांच की शुरुआत के बाद जांच विशेष को समाप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, वर्तमान मामले में एसोसिएशन ने चार याचिकाकर्ता कंपनियों की ओर से आवेदन दायर किया था जिन्हें दो देशों के विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए प्राधिकार द्वारा नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद, एसोसिएशन ने एक संबद्ध देश अर्थात् जापान के विरुद्ध आवेदन की वापसी के लिए अनुरोध किया था, परंतु दूसरे देश अर्थात् कतर के विरुद्ध जारी रखा। उसके बाद एक याचिकाकर्ता कंपनी ने सूचित किया कि वे एक संबद्ध देश अर्थात् कतर के विरुद्ध आवेदन वापस लेना चाहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनुरोध बिना दिमाग लगाए किए जा रहे हैं। जांच की शुरुआत के बाद यह आवेदकों की सनक पर नहीं हो सकता जो उन जांचकर्ता देशों को चुनें जिनके विरुद्ध जांच जारी रखने अथवा रद्द किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, जापान के विरुद्ध एएमआई द्वारा वापसी के अनुरोध को रद्द माना गया है। प्राधिकारी ने जांच आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा यथा संभव सीमा तक सत्यापित सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालने का निर्णय लिया है।

iii. जहां तक डीसीडब्ल्यू द्वारा कतर के विरुद्ध आवेदन की वापसी के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई देशों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत के बाद याचिकाकर्ता गलत ढंग से अथवा चुनिंदा रूप से व्यवहार करना शुरू नहीं कर सकता, अतः आवेदन को वापस लेने अथवा उस संबद्ध देश विशेष के विरुद्ध समर्थन करने की इच्छा नहीं रख सकता जिसका कि उसने पहले मूल से समर्थन किया हो। वे पूरे आवेदन पत्र को वापस लेकर पूरी कार्यवाही की समाप्ति के लिए आवेदन करने का निर्णय ले सकते हैं, अतः उनका यह वापस लेना चुनिंदा होने के बजाए ज्यादा विश्वसनीय लगता है तथा उनका यह आवेदन वापस लेना सनकी और पक्षपातपूर्ण लगता है। याचिकाकर्ता का आधार किसी भी पाटनरोधी जांच की आधारभूत आवश्यकता होता है तथा वे अधर में नहीं रह सकते और वे आधा मन इधर और आधा मन उधर नहीं रख सकते। यदि कोई याचिकाकर्ता आवेदन पत्र को वापस लेना चाहता है तो नियमावली के नियम 14(क) के अनुसार पूरा आवेदन पत्र वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

iv. जहां तक निर्यातकों के इस तर्क का संबंध है कि जापान के विरुद्ध वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा जापान के विरुद्ध जांच की वापसी के अनुसरण में रद्द की जानी चाहिए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह तर्क उपर्युक्त पैरा में स्पष्ट किए गए अनुसार सही नहीं है। किसी भी दशा में प्राधिकारी ने अपने दिनांक 01 सितंबर, 2017 के पत्र द्वारा अपनी स्थिति पहले ही सूचित कर दी है कि जांच के इस विलंबित स्तर पर जापान के विरुद्ध जांच को रद्द करना उचित नहीं है। यह पत्र नियम 6(7) के अनुसार सभी हितवद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया है।

v. जहां तक प्राधिकारी द्वारा अलग से की गई समीक्षा जांच से जापान को अलग किए जाने से संबंधित तर्क का संबंध है, उसे सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध दिनांक 20 नवंबर, 2017 की एसएसआर जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना 7/16/2017-डीजीएडी अधिसूचित कर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है।

vi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका गलत आंकड़ों पर आधारित है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि दिया गया यह तर्क सिद्ध नहीं है। किसी भी दशा में यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की थी और वह जांच शुरू करने के औचित्य के लिए पर्याप्त था। प्राधिकारी ने उन आंकड़ों/सूचना की परिशुद्धता एवं पर्याप्तता के संबंध में भी स्वयं को संतुष्ट कर लिया था जो नियम 5 के अनुसार जांच शुरू करने के लिए आवश्यक थी। अतः प्राधिकारी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते।

vii. जहां तक अमेरिकी डॉलर के प्रयोग के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी का यह मत है कि अमेरिकी डॉलर में पहुँच मूल्य मानक परिपाटी के अनुसार है। अमेरिकी डॉलर माप की एक यूनिट है क्योंकि यह वैश्विक रूप से स्वीकृत मुद्रा है। इस प्रकार के परिवर्तन से याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ नहीं है। प्राधिकारी ने इस विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**घरेलू उद्योग के विचार**

16. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच की अवधि के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- यह याचिका अत्यधिक गोपनीयता से प्रभावित है। याचिका में समेकित क्षति आंकड़ों के संबंध में पूरी तरह से कोई सूचना नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने उस आईएचएस रासायनिक रिपोर्ट में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जिस पर जापान के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु विश्वास किया गया है।
 - याचिकाकर्ता गोपनीय आंकड़ों के व्यवहार के संबंध में शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं।
 - याचिकाकर्ताओं ने याचिका में निहित अनिवार्य आंकड़ों के अगोपनीय सार, विशेष रूप से घरेलू उद्योग की लागत के संबंध में अथवा सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में (याचिका के अनुबंध-3.1क और अनुबंध-3.1ख) इन आंकड़ों का सार निकालने की असंभावना का औचित्य दिए बिना प्रदान किए हैं।
 - याचिकाकर्ता किसी औचित्य के बिना याचिका में निहित अधिकतर आंकड़ों का स्रोत बताने में विफल रहे। स्रोतों को प्रकट न करना भी गोपनीय व्यवहार प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे भी याचिका का समर्थन करने वाले आंकड़ों की परिशुद्धता पर अतिरिक्त संदेह बन जाता है। यदि याचिकाकर्ताओं के पास पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य थे तो उन्हें आवेदन पत्र के अगोपनीय पाठ में उन्होंने इस साक्ष्य को प्रकट किया होता।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतरण से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया।
19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना"

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

20. पाटनरोधी के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार में सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अनुच्छेद 6.5 कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि उसके प्रकटन से प्रतिस्पर्द्धी को काफी प्रतिशत लाभ होगा अथवा क्योंकि उसके प्रकटन से सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है), अथवा जो किसी जांच में एक पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई है, 28 में दिखाए गए अच्छे कारण पर प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार से माना जाएगा। इस प्रकार की सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 6.5.1 प्राधिकारी को गोपनीय सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उसके अगोपनीय सारांश की आवश्यकता होगी। ये सारांश विश्वास में प्रस्तुत सूचना के साथ की पर्याप्त समझ के अनुमति देने के लिए पर्याप्त व्यौरे में होगी। अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ऐसे पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि वह सूचना अति संवेदनशील नहीं है। ऐसी अपवादस्वरूप परिस्थितियों में कारणों का एक विवरण दिया जाना चाहिए कि सारांश संभव क्यों नहीं है।

अनुच्छेद 6.5.2 यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं और यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को या तो सार्वजनिक नहीं करना चाहता या सामान्यकृत रूप में अथवा सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करना चाहता है तो प्राधिकारी तब तक उस सूचना को महत्व नहीं देंगे जब तक कि वो उपयुक्त स्रोतों से उनकी संतुष्टि न हो जाए कि सूचना सही है।

अनुच्छेद 6.5.2 की पादटिप्पणी (पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार की पादटिप्पणी 18) में निम्नलिखित प्रावधान है:- सदस्य सहमत हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध स्वेच्छाचारी रूप से रद्द नहीं किए जाने चाहिए।"

21. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके दावों के औचित्य के संबंध में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्वचन के अनुसार कानून के विशेष प्रावधानों के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी जरूरी थी, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

सामान्य मूल्य

22. सामान्य मूल्य से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I में दिए गए हैं।
23. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संबद्ध सामानों की कुल घरेलू बिक्री के व्यौरों तथा इस तथ्य कि वे भारत में संबद्ध सामानों के निर्यात की तुलना किए जाने पर प्रतिनिधि कारक थे, की जांच की। इस बात की जांच की गई कि क्या बिक्री पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 2 के अनुसार व्यापार की सामान्य अवधि में हुई हैं। जब कभी उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के लेन-देन वार व्यौरे दिए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है तो उपर्युक्त उस सूचना पर घरेलू बाजार में बेचे गए संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास किया गया है।
24. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी और उन्हें यह सलाह दी कि वे निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से सूचना प्रदान करें। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
 - i. मैसर्स असाही ग्लास कं. लि.
 - ii. मैसर्स हीरानारायवरणम केमिकल्स एंड अलकालीज पीटीई लि.
 - iii. मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.
 - iv. मैसर्स तोसो कारपोरेशन
 - v. मैसर्स शिन-इत्सु केमिकल कं. लि.
 - vi. मैसर्स कतर विनिल कंपनी (क्यूवीसी)
 - vii. मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी.
 - viii. मैसर्स ट्रिकोन ओवरसीज इंक.

घरेलू उद्योग के विचार

25. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. जापान के मामले में सामान्य मूल्य आईएचएस केमिकल (ग्लोबल क्लोर-अलकाली) मासिक प्रकाशन में प्रकाशित कास्टिक सोडा की दरों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

- ii. औसत आयात कीमत आयात की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है। सामान्य मूल्य और एनईपी समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा व्यय के लिए समायोजित किए जाने के बाद कारखानागत स्तर पर निर्धारित किए गए हैं।
- iii. पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक नहीं है, परंतु काफी अधिक है और घरेलू उद्योग को पाटन के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।
- iv. जांच की शुरुआत के समय कतर के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों के किसी साक्ष्य के अभाव में सामान्य मूल्य कतर से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्मित किया गया है जो (क) कच्ची सामग्री, उपयोगिता और सभी अन्य लागतों के खपत कारक, घरेलू उद्योग के दक्ष उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर अपनाई गई है, (ख) कतर के लिए विद्युत की दर कतर जनरल इलैक्ट्रिसिटी एंड वाटर कारपोरेशन में उपलब्ध दर के अनुसार ली गई है और (ग) लाभ ब्याज को छोड़कर कारखानागत लागत के 5 प्रतिशत की दर से लिया गया है।
- v. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जांच की प्रगति होने पर साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार आता है। जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सूचना निर्धारण प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। साथ ही निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना पर जांच की शुरुआत के समय जोर देने की आवश्यकता नहीं होती।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोध निम्नलिखित हैं:
 - i. याचिकाकर्ता कानून के तहत निर्धारित तरीके से वर्तमान जांच में निर्यात कीमत निकालने में विफल रहे और इस प्रकार पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2(iii) के तहत अपेक्षित पाटन की मौजूदगी सिद्ध करने में विफल रहे। जापान के मामले में पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए जापान से तीसरे देशों को निर्यात पर भी विचार किया गया। निर्यात कीमत का निर्माण पाटनरोधी करार के किसी भी प्रावधान में अनुमत नहीं है।
 - ii. याचिकाकर्ताओं ने कच्ची सामग्री तथा विद्युत खपत से भारतीय उद्योग की कीमतें चुनी हैं और कतर में लागत के निर्माण के लिए विद्युत दरों हेतु अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अपनाई हैं। याचिकाकर्ताओं ने भारत में उत्पादन लागत अपनी वार्षिक रिपोर्टों में खुद ही अधिक स्वीकार की है। अतः याचिकाकर्ता ने कतर को घरेलू उद्योग की अधिक उत्पादन लागत से पाटन मार्जिन कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास किया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।
 - iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय सामान्य मूल्य के संबंध में शुद्ध एवं सत्यापन योग्य आंकड़े प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया है। जांच की शुरुआत के समय सबूत का दायित्व अलग से होता है तथा पूर्णतः याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना होता है कि संबद्ध देशों के विरुद्ध लगाए गए आरोप परिकलित सामान्य मूल्य के संबंध में विश्वसनीय है। केवल इसलिए कि क्योंकि संबद्ध देशों से सहयोगी पक्षकारों ने सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए अपने आंकड़ें दिए हैं, याचिकाकर्ता अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. आवेदक ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए आयात और आईएचएस केमिकल प्रकाशन डेटा के लिए डीजीसीआई एंड एस डेटा के आधार पर आवेदन पत्र दाखिल करने के समय साक्ष्य प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने आवेदन में प्रस्तुत सबूत की सटीकता और पर्याप्तता की जांच की और पहली नजर में निष्कर्ष निकाला कि अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार विषय जांच की शुरुआत के लिए डंपिंग, चोट और कारण संबंधी लिंक के बारे में पर्याप्त सबूत हैं, डिग्री और विषय वस्तुओं के कथित डंपिंग का प्रभाव, जापान या कतर से उत्पन्न या निर्यात किया गया।
28. प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया और उन्हें प्राधिकरण को तथ्यों / आंकड़ों की जांच करने और व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सक्षम होने के लिए प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया। रुचि के पक्ष में विशिष्ट प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से जांच की मात्रा के रूप में प्रमाण और गुणवत्ता में सुधार करती हैं।

29. प्राधिकरण ने सहकारी उत्पादक / निर्यातकों से प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं की जांच की है और सत्यापन के बाद और उपयुक्त समायोजन के बाद, सामान्य मूल्य और एक्स-कैक्टरी स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य और परिणामस्वरूप डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया गया है।

I. जापान

30. प्राधिकारी ने नोट किया कि तीन उत्पादकों और एक निर्यातक अर्थात् मैसर्स असाही ग्लास कं., मैसर्स तोसो कारपोरेशन और मैसर्स शिन-इत्सु केमिकल कं. लि. ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। उत्पादकों ने असंबंधी निर्यातक मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. ने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। प्रश्नावली के उत्तर पूर्ण हैं और तालिका अध्ययन में उचित सत्यापन के बाद स्वीकार किए गए।

क. मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. के माध्यम से मैसर्स असाही ग्लास कं. लि. सामान्य मूल्य

31. जांच की अवधि के दौरान मैसर्स असाही ग्लास ने संबंधित और असंबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध सामान बेचे हैं। यह नोट किया जाता है कि अधिकतर घरेलू बिक्री जांच की अवधि के दौरान गैर संबद्ध पक्षकारों को की गई है। घरेलू बिक्री तब पर्याप्त मात्रा में है जब भारत में निर्यात से उसकी तुलना की जाए। असाही ग्लास की लाभप्रद बिक्री कुल घरेलू बिक्री के 80 प्रतिशत से कम थी। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन पर विचार किया है। असाही ग्लास ने अंतर्देशीय भाड़ा और साख व्यय के निमित्त समायोजन का दावा किया है जिसे प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, असाही ग्लास के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य संबद्ध सामानों के लिए निर्धारित किया गया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

32. जांच की अवधि के दौरान मैसर्स असाही ग्लास कं. लि. ने मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया। मित्सुई एंड कं. लि. की बिक्री एफओबी आधार पर है। उत्पादक ने अंतर्देशीय भाड़ा, सर्वेक्षण शुल्क और साख व्यय के समायोजन का दावा किया है और उसे दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। उत्पादक के लिए निवल कारखानागत निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित की गई है।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य कीमत अमेरिकी डॉलर/मी. टन	एनईपी अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन		
				अमेरिकी डॉलर/मी. टन	%	रेंज
मैसर्स असाही ग्लास कं. लि.	मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.	***	***	***	***	1-10

ख. तोसो कारपोरेशन (उत्पादक), उसके निर्यातक मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. के माध्यम से

सामान्य मूल्य

33. मैसर्स तोसो कारपोरेशन द्वारा दायर उत्तरों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है। घरेलू बाजार में कंपनी संबंधित और असंबंधित अंतिम प्रयोक्ताओं, दोनों को संबद्ध सामानों की बिक्री करती हैं। किसी भी मामले में संबद्ध उत्पाद की बिक्री जापानी ट्रेडिंग कंपनियों (संबंधित अथवा असंबंधित) के माध्यम से अथवा ऐसे अंतिम प्रयोक्ताओं को सीधे ही की जाती है। इसी पर फिर से जांच की गई और व्यापार परीक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम पुनः स्थापित किया गया और यह पाया गया कि कुल घरेलू बिक्री के 80% से अधिक लेनदेन लाभकारी बनाने में हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने सभी बिक्री लेनदेन के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ दिया है। कंपनी ने कीमत समायोजन, अंतर्देशीय भाड़ा, सर्वेक्षण लागत, भंडारण लागत, सार संभाल लागत, बीमा लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। उत्पादक का निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

34. जांच की अवधि के दौरान मैसर्स तोसो कारपोरेशन लि. ने मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया। मित्सुई एंड कं. लि. की बिक्री एफओबी आधार पर है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, स्वीकृति एवं सार संभाल प्रभारों, विदेशी बीमा, दलाली और ऋण व्यय के निमित्त समायोजन का दावा किया है और उसे दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। उत्पादक द्वारा अपने निर्यातों के संबंध में दावा किए गए समायोजन कीमत समायोजन, अंतर्देशीय भाड़ा, सर्वेक्षण लागत, भंडारण लागत, सार संभाल लागत; बीमा लागत और अन्य एवं ऋण लागत के निमित्त हैं। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत से "अन्य" के समायोजन को स्वीकार नहीं किया है। उत्पादक के लिए निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य कीमत अमेरिकी डॉलर/मी. टन	एनईपी अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन		
				अमेरिकी डॉलर/मी. टन	%	रेंज
मैसर्स तोसो कारपोरेशन	मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.	***	***	***	***	0-5

ग. शिन-इत्सु केमिकल कं. लि., उसके निर्यातक मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. के माध्यम से

सामान्य मूल्य

35. निर्माता / निर्यातक द्वारा दायर की गई प्रश्नावली की प्रतिक्रिया घरेलू बिक्री के लिए जांच की गई है और यह पाया गया है कि कुल घरेलू बिक्री के 80% से अधिक लेनदेन लाभकारी बनाने में हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने पूर्ण बिक्री डेटा के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ दिया है। उन्होंने मात्रात्मक समायोजनों, अंतर्देशीय भाड़ा, अंतर्देशीय बीमा, भंडारण लागत, सार संभाल लागत, ऋण लागत और अन्य लागतों के निमित्त समायोजन का दावा किया है। उत्पादक का निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

36. जांच की अवधि के दौरान मैसर्स शिन-इत्सु केमिकल कं. लि. ने मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया। मित्सुई एंड कं. लि. की बिक्री एफओबी आधार पर है। उत्पादक ने लदान लागत, स्वीकृति एवं सर्वेक्षण शुल्क और ऋण व्यय के समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया गया था कि उत्पादक ने अंतर्देशीय भाड़ा (जो एफओबी लेन-देनों के लिए लागू है) के समायोजन का दावा नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने उत्पादक की निर्यात कीमत से अंतर्देशीय भाड़े के लिए समुचित समायोजन किया है। उत्पादक के लिए निवल कारखानागत निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित की गई है।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य कीमत अमेरिकी डॉलर/मी. टन	एनईपी अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन		
				अमेरिकी डॉलर/मी. टन	%	रेंज
शिन-इत्सु केमिकल कं. लि.	मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.	***	***	***	***	1-10

II. कतर

37. मैसर्स कतर विनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी. ("क्यूवीसी") (उत्पादक) ने अपने संबंधित निर्यातक कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी. के साथ विस्तृत दायर किए हैं। इसके अतिरिक्त, दो असंबद्ध निर्यातकों यथा हीरानारायवरणम केमिकल्स एंड अलकालीज पीटीई. लि., सिंगापुर और मैसर्स ट्रिक्वोन ओवरसीज इंक., पनामा ने भी अपने विस्तृत उत्तर दायर किए हैं। प्राधिकारी ने दायर उत्तरों और सभी संगत परिशिष्टों की जांच की है।

मैसर्स कतर विनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी. और मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी.

सामान्य मूल्य

38. उत्पादक और निर्यातक द्वारा दायर उत्तर की जांच की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्यूवीसी कतर में कास्टिक सोडा का एकमात्र उत्पादक है। उनकी संबंधित व्यापारी अर्थात् कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी. के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में घरेलू बिक्री है तथा सीधी बिक्री बहुत कम मात्रा में है। अधिकतर घरेलू बिक्री संबद्ध ग्राहकों को की जाती है। क्यूवीसी ने अनुरोध किया है कि घरेलू बाजार एक विशिष्ट बाजार है और मौजूदा घरेलू बिक्री की कीमतें वैश्विक बाजार स्थिति को नहीं दर्शाती हैं क्योंकि वे क्यूवीसी और उसके ग्राहकों के बीच कतिपय विशेष वाणिज्यिक मानकों के कारण विशेषताहीन रूप से बढ़ाए गए हैं। परिणामस्वरूप, क्यूवीसी ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य परिशिष्ट-I के तहत सूचित की गई घरेलू बिक्री के आधार पर परिकलित नहीं किया जाना चाहिए।
39. प्राधिकारी ने क्यूवीसी द्वारा दिए गए परिशिष्ट-I के आंकड़ों की जांच की और नोट किया कि घरेलू बाजार में बिक्री काफी लाभ मार्जिन के साथ व्यापार की सामान्य अवधि में की जाती है। अतः उचित समायोजनों को स्वीकार करने के बाद सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए घरेलू बिक्री कीमतें स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है। निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

40. क्यूवीसी केवल कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी. के माध्यम से भारत को सामानों का निर्यात करता है। मुंताजाट की भारत को निर्यात बिक्री भारत में ग्राहकों को सीधे ही की जाती है तथा असंबद्ध निर्यातकों हीरानारायवरणम केमिकल्स एंड अलकालीज पीटीई. लि., सिंगापुर और मैसर्स ट्रिकोन ओवरसीज इंक., पनामा के माध्यम से भी की जाती है।
41. मुंताजाट ने भारत को अपनी सीधी बिक्री के लिए विदेशी भाड़े, स्वीकृति एवं सार संभाल प्रभार, विदेशी बीमा, दलाली और ऋण व्यय के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उसे दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।
42. मैसर्स हीरानारायवरणम केमिकल्स एंड अलकालीज पीटीई. लि., सिंगापुर ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। उन्होंने परिशिष्ट-II में ब्यौरे दिए हैं और हीरानारायवरणम द्वारा अपने निर्यात के संबंध में दावा किए गए समायोजन, ऋण लागत तथा बैंक प्रभारों के निमित्त है। निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।
43. मैसर्स ट्रिकोन ओवरसीज इंक., पनामाने अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। उन्होंने परिशिष्ट-II में ब्यौरे दिए हैं और ट्रिकोन द्वारा अपने निर्यातों के संबंध में दावा किए गए समायोजन, कमीशन, कोरियर शुल्क, छूट ब्याज व्यय, ब्याज खर्चों, निर्यात एलसी शुल्क और समुद्री कार्गो बीमा के निमित्त है। निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अमेरिकी डॉलर/मी. टन	एनईपी अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन		
				अमेरिकी डॉलर/मी. टन	%	रेंज
कतर विनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी.	मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी.	***	***	***	***	110-120

कतर विनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी.	मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी. और हीरानायावरणन केमिकल्स एंड अलकालीज पीटीई लि.	***	***	***	***	110-120
कतर विनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी.	मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी. और मैसर्स ट्रिकोन ओवरसीज इंक.	***	***	***	***	110-120

44. यह देखा जाता है कि कतर के निर्माता / निर्यातक के लिए डंपिंग मार्जिन काफी सकारात्मक है। जबकि, जापान से उत्पादकों / निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन अर्थात् मैसर्स टोसोह कॉर्पोरेशन डंपिंग मार्जिन डी मिनिमस से नीचे है और मैसर्स असही ग्लास कं, लिमिटेड और मैसर्स शिन-इत्सू केमिकल कं. लिमिटेड के लिए डंपिंग मार्जिन पॉजिटिव है और डी मिनिमस से ऊपर है।

ख. क्षति मूल्यांकन और क्षति एवं कारणात्मक संपर्क की जांच के लिए सिद्धांत

घरेलू उद्योग के विचार

45. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए क्षति से संबंधित अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा काफी है। यह कतर के मामले में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 76 प्रतिशत तक बढ़ी है। कतर से पाटित आयातों की मात्रा क्षति की अवधि में तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में काफी बढ़ी है। जापान से आयात आधार वर्ष में नगण्य थे और फिर 2013-14 में बढ़ गए। जांच की अवधि में जांच से आयातों में काफी वृद्धि आई।
 - विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है।
 - जापान तथा कतर से आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। कतर और जापान से पाटित आयातों की मौजूदगी ने भारत में बाजार हिस्सा प्राप्त किया है जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटा है।
 - कीमत कटौती का निर्धारण केवल उन आयात लेन-देनों पर विचार कर ही निर्धारित किया जाना चाहिए जिनके आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। याचिकाकर्ता ने भी केवल उन लेन-देनों पर विचार करके कीमत कटौती का परिकलन किया है जो वस्तुतः घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे।
 - आयातों से बाजार में कीमतों का ह्रास हो रहा है, उत्पादन लागत बढ़ी है, बिक्री कीमत 2013-14 में घटी है और फिर जांच की अवधि तक आंशिक रूप से बढ़ी है। जापान से भी आयात कीमत इस अवधि में कम हुई है और कतर से आयात कीमत पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आंशिक वृद्धि के साथ क्षति की अवधि में कम हुई है। इस प्रकार, कतर और जापान से पाटित आयातों से कीमतों की वृद्धि रुकी है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हो जाती।
 - क्षति की अवधि में क्षमता बढ़ी है। उत्पादन की मात्रा भी पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है। क्षमता उपयोग भी बढ़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री अनुपात में तथा उत्पादन में वृद्धि की सीमा तक नहीं बढ़ी है। वस्तुतः बिक्री 2013-14 की तुलना में कम हुई है। परिणामस्वरूप, माल सूची का स्तर काफी रहा है।
 - घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2013-14 में बढ़ा है और जांच की अवधि में उस समय तक घटा है जब पिछले वर्ष और आधार वर्ष से उसकी तुलना की जाए तथा कतर से पाटित आयातों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कुछ कमी के साथ बढ़ा है। जापान का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में काफी बढ़ा है। जापान और कतर का बाजार हिस्सा सामूहिक रूप से काफी बढ़ा है।
 - रोजगार तथा दी गई मजदूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता उत्पादन के बीच में रही है।
 - उत्पादन के संबंध में सकारात्मक वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग में बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में नकारात्मक वृद्धि हुई है। बिक्री की लागत क्षति की अवधि में बढ़ी है। तथापि, बिक्री की कीमतें

2013-14 में कम हुई हैं और फिर जांच की अवधि तक आंशिक रूप से बढ़ीं, परंतु इस प्रकार बिक्री कीमत में वृद्धि से घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में नकारात्मक वृद्धि हुई। बिक्री की कीमत में नकारात्मक वृद्धि पाटन के कारण है।

- x. घरेलू उद्योग की वृद्धि बिक्री, बाजार हिस्सा, माल सूची, लाभ, निवेश पर आय के संदर्भ में नकारात्मक हो गई है।
- xi. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता बड़-चढ़कर आयातों की ओर जा रहे हैं।
- xii. कतर एवं जापान से आयात पाटित कीमतों पर हैं और घरेलू बिक्री कीमतों से कम पर हैं तथा उनसे मूल्यह्रास हो रहा है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घट गई है। कटौती मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी है।
- xiii. अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर या तो पहले से ही पाटनरोधी शुल्क है अथवा वे कम मात्रा में हैं, मांग बढ़ गई है, विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया है तथा कोई ऐसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित किए जा रहे/बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है तथा निर्यात प्रचालनों में क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण नहीं है। संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए उत्पादन प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी से भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xiv. मांग के संबंध में कोई न्यूनतम स्तर नहीं है। कानून संभावित प्रतिकूल प्रभाव को नहीं मानता जिसे देश ले सके, यदि उसका हिस्सा आयात में 3 प्रतिशत से अधिक है। इस मामले में, कतर से आयात 11.68 प्रतिशत है जो काफी है।
- xv. निर्दिष्ट प्राधिकारी का संबद्ध सामानों के लिए घरेलू मांग को पूरा करने हेतु घरेलू उद्योग की क्षमता से अपनी चिंता करना विशेषाधिकार नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाना भारतीय बाजार में सामानों के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं करता, वह केवल आयातित सामानों और घरेलू समान वस्तु के लिए एक व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करता है।
- xvi. घरेलू उद्योग लागत पर अपनी बिक्री कीमत तथा आयातों के पहुँच मूल्य को आधार बनाता है। वर्तमान स्थिति में जब विभिन्न अन्य स्रोतों से पाटित आयातों की मौजूदगी हो तो लाभप्रदता को एक संबद्ध देश से ही नहीं जोड़ा जा सकता। यह तथ्य कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, घरेलू उद्योग पर आयात कीमत का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता है।
- xvii. यह मानते हुए कि औसत क्षति मार्जिन कम होगा, याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे केवल उन लेन-देनों पर विचार करें जो क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए क्षति रहित कीमत से कम है। यूरोपियन कम्युनिटीज – एंटी डम्पिंग झूटीज ऑन मेलेबल कोस्ट आयरन ट्यूब अथवा ब्राजील से पाइप फिटिंग्स के मामले में डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाता है जिसमें पैनल ने यह माना कि सकारात्मक कटौती वाले लेन-देन कीमत कटौती प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निकाले जाने की आवश्यकता है। कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय अधिकरण के आदेश का भी संदर्भ दिया जाता है जिसने क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए एनआईपी से अधिक के लेन-देनों पर विचार करने की अनुमति दी थी।
- xviii. यूरोपीय समुदाय क्षति के लिए दो मार्जिन निर्धारित करता है अर्थात् कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री। एक मार्जिन अर्थात् कीमत कटौती के परिकलन के लिए लागू सिद्धांत को दूसरे अर्थात् कम कीमत पर बिक्री पर लागू न होना नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः यह तथ्य कि पाटनरोधी उपाय यूरोपीय संघ में कीमत कटौती मार्जिन के आधार पर लागू होते हैं, भी इस तर्क को सशक्त बनाता है कि क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए केवल क्षतिकारक लेन-देन पर विचार करने में कोई अड़चन नहीं है। कुल मिलाकर जब कीमत कटौती उस सीमा तक दर्शाती है जिसमें आयात कम हो रहे थे (और क्षति हुई), क्षति मार्जिन आयातों को उस सीमा तक दर्शाते हैं जहां तक क्षतिकारक रहने की संभावना हो। यदि हितवद्ध पक्षकारों का तर्क स्वीकार किया जाता है कि नकारात्मक कीमत कटौती लेन-देन कीमत कटौती के लिए समाप्त किए जा सकते हैं, परंतु क्षति मार्जिन के लिए नहीं, तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कीमत कटौती क्षति मार्जिन से अधिक है। ऐसी स्थिति उन मामलों में भी पाई जा सकती है जहां उद्योग को हानियां हो रही हैं। इस प्रकार, यदि कीमत कटौती के प्रयोजनों के लिए नकारात्मक कटौती लेन-देनों को अलग किया जाता है तो उसे क्षति मार्जिन के प्रयोजनों के लिए भी अलग किया जाना चाहिए।
- xix. यह तर्क कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक उपभोक्ता होने के नाते एल्युमिना उद्योग विचाराधीन उत्पाद की परिवहन कीमत को बढ़ाता है, इस आधार पर पूर्णतः असंगत है कि यहां तक कि अधिकतर उत्पादक पश्चिमी तट में स्थित हैं, कास्टिक सोडा के उत्पादक पूरे देश में फैले हुए हैं। पूर्व में उत्पादकों के पास *** लाख मी. टन उत्पादन क्षमता है; अतः एल्युमिना उद्योग अधिक परिवहन लागत लगाए बिना अपनी मांग आसानी से पूरा करा सकते हैं।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

46. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए क्षति से संबंधित अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- i. याचिकाकर्ताओं ने दूसरी सार्वजनिक सुनवाई में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान जांच में नकारात्मक क्षति मार्जिन है, इसलिए वर्तमान जांच में कोई शुल्क लागू नहीं किया जा सकता।
 - ii. याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए शून्य सिद्धांत को कई पैनल एवं अपीलीय निकायों की रिपोर्टों में पाटन मार्जिन का परिकलन करते समय प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार तथा व्यापार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार के अनुसार बार-बार असंगत माना गया है। डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा जिस शून्य सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया है, वह किसी तर्क से ही परे नहीं है अपितु एक स्वेच्छाचारी भी है तथा शून्य के संबंध में डब्ल्यूटीओ के जांच परिणामों के असंगत भी है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को कुछ चुनिंदा लेन-देनों के बजाए क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए जांच की अवधि के दौरान हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सभी लेन-देनों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि केवल उनको शामिल करना स्वेच्छाचारी और निर्यातकों के विरुद्ध पूर्वाग्रही होगा। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह पता लगाए कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित नए सिद्धांत को माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है और शून्य के संबंध में डब्ल्यूटीओ के जांच परिणामों का उल्लंघन है।
 - iii. कतर से संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
 - iv. एक याचिकाकर्ता के प्रबंधन में उच्च उत्पादन लागत नए ऐलिमेंट की खरीद और चीन एवं ईरान से आयात तथा उनकी वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सामने आ रही कठिनाईयों का उल्लेख किया है। जबकि एक अन्य याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क संधारणीय प्रचालन करने देने के लिए पर्याप्त हैं।
 - v. संबद्ध आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है क्योंकि बाजार में कुल मांग की तुलना में जापान से कुल आयात नगण्य है तथा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है। कुल मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा भी अधिक नहीं है और पूरी जांच की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
 - vi. तथाकथित पाटित आयातों का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की पहुँच कीमत याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। जापान से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य भी चीनी तैपई से कास्टिक सोडा के मूल्य की तरह ही होगा जहां प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि कोई कीमत कटौती नहीं थी। घरेलू उद्योग की एनआईपी तैपई के मामले की तरह समान रहेगी क्योंकि घरेलू उद्योग का घटक समान है, इस प्रकार तैपई के लिए निर्धारित नकारात्मक कीमत कटौती जापान के लिए निर्धारित सकारात्मक कीमत कटौती में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी।
 - vii. यदि बिक्री कीमत और इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया लाभ कीमत कटौती पर निर्भर था तो याचिकाकर्ताओं को आधार वर्ष, जब कीमत कटौती अत्यधिक थी, की तुलना में 2013-14 में अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए था।
 - viii. यह एक सुस्थापित परिपाटी है कि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री दोनों का परिकलन डॉलर की तुलना में मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए का प्रयोग करके किया जाता है। पहुँच मूल्य क्षति की अवधि में स्थिर रहा है, यहां तक कि यद्यपि विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव हुआ है। तथापि, कीमत में परिकल्पित कमी दर्शाने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं ने पहुँच कीमत को अमेरिकी डॉलर में भी शामिल किया है जो कि स्पष्ट रूप से वह करेंसी नहीं है जिसमें कि कोई भी भारतीय क्रेता प्रचालन करता हो।
 - ix. घरेलू उद्योग अधिकतर आर्थिक मानदंडों जैसे उत्पादन और बिक्री, प्रति वर्ष नई उत्पादन क्षमता की संस्थापना, प्रति व्यक्ति रोजगार और उत्पादकता, लाभप्रदता में सकारात्मक वृद्धि का अनुभव कर रहा है।
 - x. कीमत प्रभाव, मात्रात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक आर्थिक मानदंडों के अभाव में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो सकती। क्षति मानदंडों के संदर्भ में हास की मुख्य अवधि जांच की अवधि से पूर्व उस समय थी जब याचिकाकर्ता पाटन की मौजूदगी का आरोप नहीं लगा रहे थे और वास्तव में तब से मानदंडों में सुधार हुआ है।
 - xi. घरेलू उद्योग को क्षति का कोई खतरा नहीं है। साथ-साथ दावे अथवा वास्तविक क्षति का निर्धारण एवं वास्तविक क्षति का खतरा नहीं हो सकता क्योंकि वास्तविक क्षति के खतरे का दावा अपने आप में यह बताता है कि वर्तमान में कोई वास्तविक क्षति अथवा उसके विपरीत कोई स्थिति नहीं है। डब्ल्यूटीओ पैनल तथा यूरोपीय न्यायालयों ने यह निर्वाचन किया कि आर्थिक कारक सभी सकारात्मक हैं और उद्योग को एक मजबूत स्थिति में दर्शाया न कि टूट-फूट अथवा

- सुभेद्यता की स्थिति में, इस प्रकार क्षति के खतरे का दावा डब्ल्यूटीओ पैनल और यूरोपीय न्यायालयों के निर्वाचन के अनुसार रद्द किया जाना चाहिए।
- xii. घरेलू उद्योग पूर्ण क्षमता के साथ प्रचालन कर रहा है और बढ़ती हुई मांग को नहीं कर पा रहा है। *** प्रतिशत की अनुपयुक्त उत्पादन क्षमता नगण्य है और आवश्यक रख-रखाव प्रचालन करने के लिए ऐसे उद्योग के लिए पूरी तरह सामान्य है।
- xiii. कास्टिक सोडा उद्योग मांग में निरंतर वृद्धि के कारण भारत में बढ़ रहा है। कंपनी का इरादा कास्टिक सोडा संयंत्र की *** प्रतिशत क्षमता बढ़ाने का है। वार्षिक रिपोर्ट भी यह दर्शाती है कि भारतीय कास्टिक सोडा उद्योग कास्टिक सोडा के लिए सकारात्मक वृद्धि का अनुभव कर रहा है जो आगामी वर्षों में भी जारी रहेगा। साथ ही जो अन्य भारतीय उत्पादक इस याचिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वे भी सकारात्मक निष्पादन देख रहे हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती।
- xiv. यदि जल्दीबाजी में 8 देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के बावजूद अन्य देशों के मूल के आयातों से कोई क्षति होती है तो जांच की अवधि के दौरान आयात बढ़े हैं जबकि पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले देशों से आयात 60 प्रतिशत नीचे आए हैं जो 5,757 एमटी के निम्न स्तर पर पहुँच गए हैं।
- xv. पाटन और तथाकथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है। याचिकाकर्ता को कास्टिक सोडा के लगभग सभी स्रोतों पर तेरह वर्ष के शुल्क के बाद भी क्षति हो रही है, तो यह स्पष्ट है कि क्षति का तथाकथित रूप से पाटित आयातों से कोई संबंध नहीं है बल्कि यह अन्य कारकों यथा क्लोरीन के निष्पादन के परिणामस्वरूप है। याचिकाकर्ता उनको हुई क्षति के लिए झूठ-मूठ ही संबद्ध देशों पर आरोप लगा रहे हैं।
- xvi. घरेलू उद्योग को हुई हानियों और जापान से आयात के बीच कोई सह संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग ने 2014-15 में अपने सबसे खराब लाभ सूचित किए हैं जब जापान में आयात शून्य थे।
- xvii. घरेलू उद्योग को संरचनात्मक समस्याओं से नुकसान होता है। भारत में 34 कंपनियां हैं जिनमें से केवल 10 याचिकाकर्ता हैं, शेष उत्पादकों ने अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने की व्यवस्था की है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कास्टिक सोडा के अधिकतर भारतीय उत्पादकों को जापान से आयात अपने व्यापार को खतरा पैदा करने वाले नहीं दिखाई देते।
- xviii. लगभग एक मिलियन टन प्रति वर्ष का भारी मांग आपूर्ति अंतराल है। अतः विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता के पास आयात का सहारा लेकर इस अंतराल को पूरा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
- xix. जापान से आयात द्वारा पूरी की गई मांग बहुत अधिक नहीं है और यह कुल मांग का केवल 2.5 प्रतिशत है।
- xx. भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी तट को कास्टिक सोडा के परिवहन से अनावश्यक कठिनाईयां होती हैं तथा एल्युमिना विनिर्माताओं को कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप, अन्य देशों से कास्टिक सोडा की मांग बनती है जहां परिवहन की लागत कम है तथा भारी मात्रा में आपूर्ति होती है जिससे एल्युमिना उद्योग के लिए कच्ची सामग्री (कास्टिक सोडा) की कम लागत बनती है। इसके परिणामस्वरूप, सभी अर्थक्षम स्रोतों से मांग में वृद्धि होती है जो एल्युमिना प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित भारी मात्रा में आपूर्ति के लिए घरेलू उत्पादों की अर्थक्षमता के कारण भी है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

47. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) के अनुसार की जानी होती है जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:
- "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"*
48. प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण में वर्तमान जांच की अवधि के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों का नीचे समाधान किया गया है।
49. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर बाधा डालने वाली उन बातों पर विचार किया है जो उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा

तथा क्षति आदि से संबंधित है और यह उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसार किया गया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 तथा डीजीएडी की स्थापित परिपाटियों के अनुसार क्षति रहित कीमत का परिकलन किया है।

I. मांग का मूल्यांकन

50. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने सभी स्रोतों से आयातों तथा आवेदक की घरेलू बिक्री की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की स्पष्ट खपत अथवा मांग परिभाषित की है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	9,69,113	10,38,253	9,88,766	10,11,106
2	अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	15,58,513	15,79,744	18,25,113	18,54,952
3	संबद्ध देश	मी. टन	31,591	68,120	57,003	1,54,768
(i)	जापान	मी. टन	42	36,248	-	99,302
(ii)	कतर	मी. टन	31,549	31,872	57,003	55,466
4	पाटनरोधी शुल्क वाले देश	मी. टन	2,57,624	2,34,759	3,33,855	3,14,362
5	अन्य देश	मी. टन	14,272	1,595	15,799	5,757
6	मांग/खपत	मी. टन	28,31,112	29,22,472	32,20,537	33,40,945

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग पूरी क्षति की अवधि में निरंतर बढ़ी है। कुल घरेलू मांग में भारतीय उत्पादकों का हिस्सा 86 प्रतिशत है और संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा 4.6 प्रतिशत है। संबद्ध सामानों की घरेलू मांग का दूसरा 9.4 प्रतिशत हिस्सा उन देशों से आयातित किया जा रहा है जिनके विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है।

II. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

52. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच की अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में किया गया है:

क्रम सं.	आयात	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	कुल आयात	मी. टन	3,03,486	3,04,474	4,06,657	4,74,887
2	संबद्ध देश	मी. टन	31,591	68,120	57,003	1,54,768
(i)	जापान	मी. टन	42	36,248	0	99,302
(ii)	कतर	मी. टन	31,549	31,872	57,003	55,466
3	पाटनरोधी शुल्क वाले देश	मी. टन	2,57,624	2,34,759	3,33,855	3,14,362
4	अन्य देश	मी. टन	14,272	1,595	15,799	5,757
आयात में बाजार हिस्सा						
1	संबद्ध देश	%	10	22	14	33
(i)	जापान	%	0	12	0	21
(ii)	कतर	%	10	10	14	12
2	पाटनरोधी शुल्क वाले देश	%	85	77	82	66
3	अन्य देश	%	5	1	4	1

4	कुल	%	100	100	100	100
के संबंध में आयात						
1	- उत्पादन	%	2.93	5.95	4.57	11.62
2	- मांग	%	1.12	2.33	1.77	4.63

53. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि जापान से संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि में पूर्ण रूप से काफी बढ़ा है। जांच की अवधि के दौरान आयात आधार वर्ष में शून्य से बढ़कर 21 प्रतिशत तक ऊपर चले गए हैं। कतर से आयात से उस समय कमी नजर आई जब उनकी तुलना पिछले वर्ष से की गई, जबकि आधार वर्ष से तुलना करने पर वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान कुल आयात समान स्तर पर रहे हैं।

III. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

54. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत से तुलना करने पर तथाकथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में कीमतों पर मंदी का प्रभाव डालेगा अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकेगा जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत में मंदी और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत से की गई है।

क. कीमत कटौती

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत से तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में कीमतों पर मंदी का प्रभाव डालेगा अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकेगा जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती। इस संबंध में व्यापार के समान स्तर पर उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत सभी निवल छूट और करों के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	जापान	कतर	संबद्ध देश
1	आयात की आधार कीमत	रु./मी. टन	24,955	24,944	24,953
2	निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***
3	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***
4	कीमत कटौती(%)	%	***	***	***
5	कीमत कटौती	रेंज	5-15	5-15	5-15

56. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमतें (डीजीसीआई और एस के अनुसार) घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम हैं। परिणामस्वरूप, सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख. कम कीमत पर बिक्री

57. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की द्रव एवं फ्लेक के रूप में अलग-अलग जांच की है। घरेलू उद्योग के लिए आंकलित भारित औसत क्षति रहित कीमत की तुलना निम्नलिखित रूप में पाटित आयातों के कम बिक्री प्रभाव की जांच करने के लिए संबद्ध देश से आयात की पहुँच कीमत के साथ की गई।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	जापान	कतर
1	आयात मात्रा	मी. टन	99,302	55,466
2	क्षति रहित कीमत	अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन	***	***
3	आयात की आधार कीमत	अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन	24,955	24,944
4	कम कीमत पर बिक्री	अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन	(***)	(***)
5	कम कीमत पर बिक्री	%	(***)	(***)
6	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	(5)-5	(5)-5

58. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग पर कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव कतर एवं जापान से नकारात्मक है। यह इंगित करता है कि जिन देशों में विषय देशों से आयात भारत में उतर रहे हैं (डीजीसीआई और एस के आंकड़ों के मुताबिक) घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से अधिक है।

ग. कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण

59. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतें कम करने के लिए अथवा तथा कीमतों का बढ़ना रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुआ होता। प्राधिकारी ने निम्नलिखित व्यौरे के अनुसार क्षति की अवधि में लागत एवं कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	आयात की आधार कीमत	रु./मी. टन	25,392	25,235	23,721	24,953
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	93	98
3	आधार कीमत - पाटनरोधी शुल्क वाले देश	रु./मी. टन	26,751	25,320	24,672	25,568
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	92	96
5	बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	113	112
7	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	98	100

60. उपर्युक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयात का पहुँच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में आंशिक रूप से कम हुआ है। बिक्री की कीमत आधार वर्ष तथा पूर्व वर्ष की तुलना में समान स्तर पर रही है; तथापि, 2013-14 के दौरान कम हुई है। आधार वर्ष और साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री मूल्य उसी स्तर पर रहा है; हालांकि, 2013-14 के दौरान गिरावट आई है। चोट की अवधि के दौरान बिक्री की लागत में वृद्धि हुई और विशेषकर जब आधार वर्ष की तुलना में। इस प्रकार, उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग बिक्री मूल्य में वृद्धि करने में असमर्थ है, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया जाता है और निराश होता है। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि बिक्री की कीमत हमेशा चोट अवधि और पीओआई में बिक्री की लागत से ऊपर होती है, जो यह दर्शाती है कि कम मूल्य के आयात के बावजूद, घरेलू उद्योग उच्च बिक्री मूल्य को महसूस करने में सक्षम है।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

61. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली में यह प्रावधान भी है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजारहिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।
62. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

क. बाजार हिस्सा

63. आयात के व्यौरे, घरेलू बिक्री और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	कुल मांग / उपभोग	मी. टन	28,31,112	29,22,472	32,20,537	33,40,945
2	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	9,69,113	10,38,253	9,88,766	10,11,106
3	अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	15,58,513	15,79,744	18,25,113	18,54,952
4	संबद्ध देश	मी. टन	31,591	68,120	57,003	1,54,768
5	हिस्सा					
5a	घरेलू उद्योग की	%	34.23	35.53	30.70	30.26
5b	अन्य उत्पादकों	%	55.05	54.06	56.67	55.52
5c	संबद्ध देश	%	1.12	2.33	1.77	4.63
(i)	जापान	%	0.00	1.24	-	2.97
(ii)	कतर	%	1.11	1.09	1.77	1.66

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, जो 2013-14 में बढ़ा, उसके बाद काफी घटा है। तथापि, संबद्ध आयात काफी बढ़े हैं। यह दर्शाता है कि उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को प्रभावित कर रहा है। तथापि, अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा भी काफी अधिक है। अतः आयातों के प्रभावों की मात्रा बताना कठिन है जो कि घरेलू बाजार में कुल मांग के 5 प्रतिशत से कम है।

ख. उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	संस्थापित क्षमता	मी. टन	1,206,050	1,297,543	1,410,650	1,445,800
2	उत्पादन	मी. टन	1,076,792	1,144,178	1,247,463	1,331,558
3	क्षमता उपयोग	%	89.28	88.18	88.43	92.10
4	घरेलू बिक्री	मी. टन	969,113	1,038,253	988,766	1,011,106

65. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है तथा घरेलू बाजार में मांग भी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, बिक्री और क्षमता उपयोग, दोनों मांग में वृद्धि के अनुरूप आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़े हैं।

ग. माल सूची

66. संबद्ध सामानों की माल सूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	आरंभिक	मी. टन	***	***	***	***
2	अंतिम	मी. टन	***	***	***	***
3	औसत	मी. टन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	127	90

67. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग के साथ घरेलू बाजारों की सूची घरेलू उद्योग के लिए बेहतर स्थिति का संकेत दे सकती है, हालांकि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है, हालांकि आदान-प्रदान घरेलू उद्योग के लिए चोट के निर्णायक संकेतक नहीं हैं।

घ. लाभ तथा नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

68. लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर आय से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	113	112
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	98	100
5	लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	42	57
7	आरओआई	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	41	58
9	नकद लाभ	रुपए लाख	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	57	72

69. लाभ/हानि तथा नकद प्रवाह के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि कर पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता क्षति की अवधि में कम हुई है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

70. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित रूप में दर्शाए गए हैं:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
1	कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
1a	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	105	106

2	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
2a	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	110	117
3	मजदूरी	रुपए लाख	***	***	***	***
3a	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	136	151

71. यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादकता और मजदूरी क्षति की अवधि में बढ़े हैं जो घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण जो किसी हद तक हो सकती है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि से बेहतर दक्षता का संकेत मिलता है और मजदूरी में वृद्धि समय के साथ सामान्य बाजार परिस्थितियों के प्रगतिशील राज्य के जवाब में हो सकती है।

च. पाटन की मात्रा

72. डंपिंग की भांति उस हद तक का एक संकेत है, जिसके लिए घरेलू आयात में गिरावट आती है जिससे घरेलू उद्योग को प्रभावित किया जा सकता है। उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि कतर के निर्यात / निर्यातक के लिए डंपिंग मार्जिन काफी सकारात्मक है। जबकि, जापान से उत्पादकों / निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन अर्थात् मैसर्स टोसोह कॉर्पोरेशन डंपिंग मार्जिन डी मिनिमस से नीचे है और मैसर्स असही ग्लास कं, लिमिटेड और मैसर्स शिन-इत्सू केमिकल कं, लिमिटेड के लिए डंपिंग मार्जिन पॉजिटिव है और डे मिनिमस से ऊपर है।

छ. वृद्धि

73. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में मात्रात्मक मानदंडों के संदर्भ में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है, तथापि, कीमत संबंधी मानदंडों के संबंध में वृद्धि प्रतिकूल रही है।

ज. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान क्षमताएं बढ़ाई हैं तथा नए निवेश किए हैं। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि संबद्ध देशों से आयात के कारण वे बढ़ी हुई क्षमताओं की पूर्ण संभावना लेने में असमर्थ थे। हालांकि, यह देखा गया है कि उनकी क्षमता उपयोग 92% से ऊपर है और वर्तमान विश्लेषण के साथ यह निष्कर्ष नहीं लगाया जा सकता है कि पूंजी निवेश को बढ़ाने की उनकी क्षमता प्रभावित हो गई है।

झ. घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

75. यह जांच दर्शाती है कि संबद्ध सामानों के लिए भारत में अच्छी मांग है। संबद्ध देशों से पाटित आयात कीमतें घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे ही प्रभावित कर रही हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य (डीजीसीआई और एस डेटा के अनुसार) घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास/न्यूनीकरण किया जिससे उन्हें वित्तीय हानियाँ हुईं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि विषय देशों के अलावा अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात जहाँ कोई भी विज्ञापन नहीं है, घरेलू उद्योग को घायल नहीं कर रहे हैं उत्पाद की मांग बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रही है और इसलिए, घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट और दमन के लिए जिम्मेदार कोई कारक नहीं हो सकता था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योगों के उदास और दबदबे की कीमतों के लिए विषय देशों से पड़ी हुई वस्तुओं जिम्मेदार हैं। हालांकि, इसे सीधे अनुमानित नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी काफी महत्वपूर्ण है और आयात का हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम है।

iv. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संपर्क

76. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की शुरुआती क्षति, मात्रात्मक और कीमत प्रभाव को सिद्ध करने में वास्तविक क्षति और मंदी का मौजूदगी की जांच करने पर भारतीय नियमावली तथा पाटनरोधी करार के तहत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मानदंडों की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

- क. **तीसरे देशों से आयात की मात्रा तथा कीमतें:** चीन जन गण, कोरिया आरपी, नॉर्वे, थाईलैंड, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है।
- ख. **मांग में प्रवृत्ति** क्षति की अवधि में मांग निरंतर बढ़ी है। तथापि, पूर्व वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पाटित आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है जिसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- ग. **अन्य उत्पादों का निष्पादन** घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन का संबद्ध उत्पाद के सूचित निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, अन्य कारकों के कारण क्षति, यदि कोई हो, को याचिकाकर्ता द्वारा अलग किया गया है।
- घ. **खपत के पैटर्न में बदलाव** विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। अतः इस कारण से खपत के पैटर्न में बदलाव को यह नहीं माना जा सकता है कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ङ. **विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा** ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता हो।
- च. **प्रौद्योगिकी में विकास** संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से, प्रौद्योगिकी में विकास को ऐसा कारक नहीं माना जा सकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा हो।
- छ. **निर्यात निष्पादन** घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति पूर्ण रूप से घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने समग्र क्षति की अवधि के दौरान कुछ निर्यात किए हैं। हालांकि, इस कारक को यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ज. **उत्पादकता** घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग की उत्पादकता में हास के कारण नहीं हुई है।

झ. **क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन**

77. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के संदर्भ में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत की जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यात के पहुँच मूल्य के साथ तुलना की गई है और इस प्रकार निकाला गया क्षति मार्जिन निम्नलिखित है:

क्रम सं.	उत्पादक	निर्यातक	आधार मूल्य	क्षति रहित कीमत	क्षति मार्जिन		
			अमेरिकी डॉलर /मी. टन	अमेरिकी डॉलर /मी. टन	अमेरिकी डॉलर /मी. टन	%	रेंज
	जापान						
1	मैसर्स असाही ग्लास कं. लि.	मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.	***	***	(***)	(***)	(5)-5
2	मैसर्स तोसो कारपोरेशन	मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.	***	***	***	***	0-5
3	शिन-इत्सु केमिकल कं. लि.	मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि.	***	***	***	***	0-5
	कतर						
4	कतरविनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी.	मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी	***	***	***	***	0-5

क्रम सं.	उत्पादक	निर्यातक	आधार मूल्य	क्षति रहित कीमत	क्षति मार्जिन		
		(मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी.					
5	कतरविनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी.	मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी. और हीरानायावरणन केमिकल्स एंड अलकालीज पीटीई लि.	***	***	(***)	(***)	(5)-5
6	कतरविनिल कंपनी लिमिटेड क्यू.एस.सी.	मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंताजाट) क्यू.जे.एस.सी. और मैसर्स ट्रिकोन ओवरसीज इंक.	***	***	(***)	(***)	(10)-(1)

स. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

78. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। उनमें उठाए गए मुद्दे जांच के दौरान पूर्व में पहले ही उठा दिए गए हैं और संगत पैराओं में उनका समाधान भी कर दिया गया है। तथापि, स्पष्टतः के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की जा रही है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

79. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे परिकलित पाटन मार्जिन के संबंध में सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रुपांतर प्रकट करें।
- यह अनुरोध है कि याचिकाकर्ता ने जापान के विरुद्ध जांच रद्द करने का अनुरोध नहीं किया था। हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया था कि जापान के विरुद्ध जांच की शुरुआत कानूनी दृष्टि से बुरी थी क्योंकि जापान के विरुद्ध शुल्क पूर्व में समाप्त की गई जांच में शून्य दर पर जारी थे। इस तर्क पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं ने जापान के विरुद्ध जांच रद्द करने के लिए आवेदन किया था। हितबद्ध पक्षकारों ने जापान के विरुद्ध याचिका को वापस लेने के संबंध में अपनी स्थिति बदल दी है। तथापि, प्राधिकारी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
- यह अनुरोध है कि जापान के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन आईएचएस केमिकल में प्रकाशित कीमतों के आधार पर परिकलनों की तुलना में बहुत कम है। आईएचएस केमिकल की कीमतों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पाटन मार्जिन परिकलन और निर्यातकों के उत्तरों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित परिकलन में अंतर के लिए कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रतीत नहीं होता। जापान के उत्तरदाता निर्यातक जापान में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आईएचएस केमिकल में प्रकाशित कीमतें आदर्श रूप से संबद्ध देश में मौजूद कीमतों की प्रतिनिधि होनी चाहिए। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यातकों द्वारा कुछ तथ्यों को छिपाया गया है।
- यह अनुरोध है कि निर्धारित एनआईपी बहुत कम है जिससे अपर्याप्त क्षति मार्जिन हो रहा है।
- अनुबंध-III के तहत कच्ची सामग्री और उपयोगी वस्तुओं का अदक्ष उपयोग ही प्रासंगिक किए जाने की आवश्यकता है। कच्ची सामग्री में अधिकृत परिवर्तनों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल जब प्राधिकारी यह पाए कि उपभोग इनपुट के अदक्ष उपयोग के परिणामस्वरूप है तो प्राधिकारी उसे प्रासंगिक बना सकता है।

- ख. उत्पादन की वास्तविक लागत निर्धारित की जानी चाहिए न कि उस कीमत का निर्धारण करने के लिए उत्पादन की राष्ट्रीय न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाए जिसकी क्षति मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए आयात कीमत के साथ तुलना की जा सके।
- ग. लगाई गई पूंजी निर्धारित परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए अथवा अचल परिसंपत्तियों के न्यूनतम सकल मूल्य पर निर्धारित की जानी चाहिए। वस्तुतः इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त मूल्य निवेशों का वर्तमान मूल्य है।
- व. यह अनुरोध है कि कीमत कटौती और क्षति मार्जिन, क्षति कारक लेन-देनों पर ही विचार करते हुए अर्थात् उन लेन-देनों पर विचार करते हुए जिनके आयात का पहुँच मूल्य याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित घरेलू मूल्य की बिक्री कीमत से कम है, परिकलित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत यूरोपीय समुदाय – ब्राजील से मालेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग संबंधी पाटनरोधी शुल्क, के मामले में डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट में भी लागू किया गया है।
- vi. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है, जैसा कि जारी प्रकटन से स्पष्ट है।
- vii. यूएस/मी.टन में व्यक्त पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने हेतु पाटनरोधी शुल्क के निर्धारित रूप की आवश्यकता है। आयात कीमत का सत्यापन करना पत्तन प्राधिकारियों के लिए न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, इस प्रकार शुल्क ऐसे तरीके से लगाया जाना चाहिए जहां यह बेकार न हो।

विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

80. विभिन्न विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध सारभूत रूप से निम्नलिखित हैं:

- i. यह अनुरोध है कि अत्यधिक गोपनीयता और इस सीमा तक दिए गए आंकड़ों, जिनका कोई सार्थक विश्लेषण नहीं किया जा सकता, के संबंध में याचिका में गंभीर विसंगतियां हैं।
- ii. यह अनुरोध है कि प्राधिकारी ने उत्पादक अर्थात् मैसर्स कतर विनाइल कंपनी (क्यूवीसी) के लिए टेढ़े और बड़े हुए पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया था जो कि त्रुटिपूर्ण है और वास्तविक नहीं है तथा उत्पादक के अनुरोध की उपेक्षा की है कि घरेलू बिक्री साधारण व्यापार की अवधि में क्यों नहीं है तथा उन्हें सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्यों नहीं माना जाना चाहिए। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि उसे बाजार विशेष की स्थिति को मानने और उस पर विचार करने पर ध्यान न देते हुए स्वीकार क्यों नहीं किया गया है।
- iii. मैसर्स तोसो कारपोरेशन ने उत्पादन लागत के परिकलन पर विवाद किया है जो व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि में विफल रहा। प्राधिकारी को चाहिए कि वे उत्पादक द्वारा दिए गए व्यौरों के अनुसार विस्तृत लागत परिकलनों की पुनः जांच करें। इसके अतिरिक्त, कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात लागत के परिकलन के लिए समायोजनों की भी पुनः जांच की जाए और निर्यातकों द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार किया जाए।
- iv. यह अनुरोध है कि कतर से नकारात्मक कम कीमत पर बिक्री है, अतः कम कीमत पर बिक्री के बिना कीमत क्षति नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध है कि कतर से और विशेष रूप से सहयोगी चैनल से किए जा रहे निर्यातों से घरेलू उद्योग को कोई पाटन एवं क्षति नहीं है।
- v. यह अनुरोध है कि जापान से व्यापार चैनल में शामिल सभी निर्यातकों और उत्पादकों ने विधिवत रूप से भाग लिया है और सभी अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, सहयोगी निर्यातक एवं उत्पादकों से कोई पाटन एवं क्षति नहीं है, अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि सहयोगी निर्यातकों एवं उत्पादकों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के लिए कोई शुल्क न लगाएं।
- vi. यह अनुरोध है कि क्षति की अवधि के दौरान तथा उसी अवधि के दौरान जापान से किए गए आयातों के आर्थिक मानदंडों के विश्लेषण के संदर्भ में क्षति में कारणात्मकता का अभाव है।
- vii. लगाई गई पूंजी पर आय पर 22 प्रतिशत की दर किसी तर्कसंगत आधार पर नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

81. यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटन पश्चात् स्तर पर उठाए गए मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त संगत पैराओं में पहले ही जांच कर ली गई है, तथापि, अनुरोधों की स्पष्टतः के लिए उनका समाधा

- i. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उनके दावों के औचित्य तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन किए गए अनुसार कानून के विशेष प्रावधानों के संबंध में की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।
- ii. याचिका की वापसी तथा जांच को रद्द किए जाने के मुद्दों को उपर्युक्त संगत पैराओं में विस्तार से लिया गया है।
- iii. प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा दी गई विस्तृत सूचना/आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आईएचएस से सूचना पर विश्वास किया है और उचित सत्यापन के बाद उसे स्वीकार किया गया है।
- iv. जहां तक एनआईपी के परिकलन का संबंध है, प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि एनआईपी और उत्पादन लागत निदेशालय में अपनाई जा रही परिपाटी तथा नियमावली के अनुसार निर्धारित की गई है।
- v. कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है तथा क्षतिकारक लेन-देनों के आधार पर ही उसका परिकलन करने की याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार नहीं की जाती है।
- vi. प्राधिकारी ने मैसर्स कतर विनाइल कंपनी (क्यूवीसी) की घरेलू बिक्री को स्वीकार किया है क्योंकि यद्यपि अत्यधिक लाभ मार्जिन हैं, तथापि, व्यापार की सामान्य अवधि में लेन-देन किए गए हैं। निर्यातक के सामान्य मूल्य को रद्द करने की मांग करते हुए इस संबंध में निर्यातक का अनुरोध असामान्य है, अतः उसे रद्द किया जाता है।
- vii. प्राधिकारी ने मैसर्स तोसो कारपोरेशन, जापान की उत्पादन लागत की पुनः जांच की है और उसका पुनः परिकलन किया है तथा यह पाया है कि 80 प्रतिशत से अधिक घरेलू बिक्री लेन-देन लाभप्रद हैं और इसीलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सभी बिक्री लेन-देनों के आधार पर किया है।
- viii. जहां तक मैसर्स तोसो कारपोरेशन, जापान की निवल निर्यात कीमत के परिकलन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि उसे उपर्युक्त संगत पैराओं में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि निर्यातक द्वारा दावा किया गया समायोजन और दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये समायोजन भाड़ा स्वीकृति एवं सार संभाल प्रभार, समुद्री बीमा, दलाली और ऋण व्यय के निमित्त थे। तथापि, जिन समायोजनों का निर्यातक ने दावा किया है, परंतु प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं, वे सर्वेक्षक लागत, भंडारण लागत, सार संभाल लागत, बीमा लागत, अन्य एवं ऋण लागत के निमित्त थे। यह जापान के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा मांग किए गए समायोजनों और स्वीकार किए गए समायोजनों की तुलना के आधार पर है।
- ix. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर कम कीमत पर बिक्री का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वह नकारात्मक है। तथापि, कतर के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े एक चैनल में काफी पाटन मार्जिन, परंतु बहुत कम क्षति मार्जिन दर्शाते हैं और असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात के मामले में नकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाते हैं।
- x. जहां तक घरेलू उद्योग के आर्थिक कारकों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि उनकी जांच प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम के संगत पैराओं में सावधानीपूर्वक की गई है।

ज निष्कर्ष

82. उठाए गए मुद्दों की जांच करने और इच्छुक पार्टियों और तथ्यों द्वारा किए गए सबमिशन के बाद इस शोध में दर्ज प्राधिकरण से पहले उपलब्ध कराया गया, प्राधिकरण निष्कर्ष निकाला है कि:

- i. विचार के तहत उत्पाद कतर से भारत में निर्यात किया गया है, इसकी सामान्य कीमत की तुलना में काफी गिरावट की कीमतों में निर्यात किया गया है, हालांकि, घरेलू उद्योगों के लिए सामग्री चोट नहीं पैदा कर रहे हैं।
- ii. विचाराधीन उत्पाद मैसर्स असही ग्लास कं, लिमिटेड जापान द्वारा भारत में निर्यात किया गया है, जो कीमतों में गिरावट पर है, लेकिन घरेलू उद्योगों के लिए सामग्री की चोट नहीं पैदा हो रही है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद मैसर्स टोसोह कॉर्पोरेशन जापान द्वारा भारत में निर्यात किए गए कीमतों पर निर्यात किया गया है जो कि उत्पादक के सामान्य मूल्य से मामूली कम है और डंपिंग मार्जिन डी मिनिमस से नीचे है। इसके अलावा, मैसर्स टोसोह कॉर्पोरेशन के कारण घरेलू उद्योग की वजह से सामग्री की चोट मामूली है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद, मैसर्स शिन-इत्सु केमिकल कं, लिमिटेड द्वारा भारत में निर्यात किए गए हैं, जो कीमतों पर मामूली कम है जो कि निर्माता के सामान्य मूल्य से कम है, हालांकि, डंपिंग मार्जिन और चोट के मार्जिन नगण्य हैं और इसलिए नहीं घरेलू उद्योग में भौतिक चोट के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- v चोट विश्लेषण इंगित करता है कि घरेलू उद्योग चोट से पीड़ित नहीं है और विषय देशों से कथित रूप से आयात किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को भौतिक चोट नहीं पहुंचे।

डं सिफारिश

83. प्राधिकरण का कहना है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था और डंपिंग, चोट और साझे लैंक के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी देने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। एडी नियमों के संदर्भ में डंपिंग, चोट और उसके कारणों की जांच शुरू करने और आयोजित करने के बाद यह स्थापित किया गया है कि कथित तौर पर डंपि दिया गया आयात घरेलू उद्योग के लिए भौतिक चोट नहीं पैदा कर रहा है। प्राधिकरण का मानना है कि मौजूदा जांच में एंटीडिंग झूठी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण नियमों के नियम 14 (बी) के अनुसार जांच की समाप्ति की सिफारिश करने के लिए उचित मानता है।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Department of Commerce

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi, the 10th January, 2018

NOTIFICATION

Final Findings

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Caustic Soda originating in and exported from Japan and Qatar.

F. No. 14/31/2015-DGAD: Whereas Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), on behalf of the domestic producers of caustic soda, along with 4 producers of the subject goods, i.e., M/s DCW Ltd, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., M/s Grasim Industries Ltd., and SIEL (hereinafter referred to as the "applicant" or "Domestic Industry") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Caustic Soda" originating in or exported from Japan and Qatar (hereinafter also referred to as subject countries).

1. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No. 14/31/2015-DGAD dated 14th October, 2016, published in the Gazette of India, initiating the subject investigations in accordance with the Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from Japan and Qatar to recommend the amount of anti- dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

A. PROCEDURE

2. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants on behalf of the domestic industries, alleging dumping of Caustic Soda originating in or exported from Japan and Qatar.
 - ii. The Authority notified the Embassy of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

- iii. The Authority issued a notification dated 14th October, 2016, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
- iv. The Embassy of the subject countries in India was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within prescribed time limit.
- v. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Asahi Kasei Chemicals Corp.
 - ii. PECCO Ltd
 - iii. Asahi Glass Company Seimi Chemical Co. Ltd.
 - iv. Tokuyama Corp.
 - v. Qatar Vinyl Company Ltd. QSC
 - vi. Sannou Co. Ltd.
 - vii. TOSOH Organic Chemical Co. Ltd.
 - viii. Kaneka Corp.
- vi. In response to the above notification, following exporters/ producers have submitted exporter questionnaire responses.
 - i. M/S. Asahi Glass Co., Ltd, Japan
 - ii. M/s Hiranyavarnaam Chemicals & Alkalis Pte Ltd, Singapore
 - iii. M/s Mitsui & Co., Ltd., Japan
 - iv. M/s Tosoh Corporation, Japan
 - v. M/s Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Japan
 - vi. M/s Qatar Vinyl Company (Qvc)
 - vii. M/s Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat)Q.J.S.C.
 - viii. M/s Tricon Overseas Inc., Panama
- vii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Abhay Chemicals Ltd.
 - ii. Arvind Mills Ltd.
 - iii. Central Pulp Mills Ltd.
 - iv. Godrej Sopas Ltd.
 - v. Gujrat State Fertilizer & Chemicals Ltd.
 - vi. Indian Oil Corp Ltd.
 - vii. Link Pharma Ltd.
 - viii. Narmada Chemature Petrochemicals Ltd.
 - ix. Pab Chemicals (p) Ltd.

- x. Rubamin Ltd.
- xi. Torrent Gujrat Biotech Ltd.
- xii. Birla Cellulose Ltd.
- xiii. Deepak Nitrite Ltd.
- xiv. Gujrat Narmada Fertilizer & chemicals Ltd.
- xv. Indian Farmer Fertilizer Corp. Ltd.
- xvi. Jaysynth Dyechem Ltd.
- xvii. Meghmani Organics Ltd.
- xviii. Nirma Ltd.
- xix. Rama News Prints & Papers Ltd.
- xx. Sabero Organics Ltd.
- xxi. Trranspek Silox Industries Ltd.
- xxii. National Aluminium Company Ltd.
- xxiii. Hitsu Industries Ltd.
- xxiv. Adani Wilmar Ltd.
- xxv. Shri Ramchandra Straw Products Ltd.
- xxvi. Daurate Organics Ltd
- xxvii. Harish Kr. & Company
- xxviii. Hindustan Lever Ltd.
- xxix. Cyanides & Chemicals Company
- xxx. Adani Exporters Ltd.
- xxxi. Libra Foams
- xxxii. Bilag Industries Pvt Ltd.
- xxxiii. CJ Shah & Co.
- xxxiv. Hindustan Link & Resins Ltd.
- xxxv. Alkalies Manufacturers Association of India

viii. The following importers/users have submitted importers questionnaire responses:

- i. Nalco
- ii. Vedanta Ltd.

- ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
- x. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xi. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if antidumping duty lower than the dumping margin would be

sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Antidumping Rules.

- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
- xiii. The Authority held an oral hearing on 22nd August, 2017 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6 (6), which was attended by the representatives of Domestic Industry and the opposing interested parties. The representatives of Domestic Industry and the interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally.
- xiv. The last date for issue of Final finding was 13th October, 2017, however the same was extended for three months by Central Government in terms of Rule 17(1)(a) upto 13th January, 2018.
- xv. Due to change of the Designated Authority and in line with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the ATMA case, another oral hearing was conducted by the new Designated Authority on 30th October, 2017. The parties, who presented their views in the 2nd oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvi. Verification of the information provided by the petitioner companies, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present Final Findings.
- xvii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 31st March 2016 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the Period of Investigation (POI).
- xviii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the POI. The Authority has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority have been addressed in this Final Finding.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xxi. A Disclosure Statement was issued on 26.12.2017 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 04.1.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxii. ***in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted for the present investigation is 1 US\$ = Rs. 65.91.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**Views of the Domestic Industry**

3. The views of the Domestic Industry are as follows:

- i. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda, in all forms.
- ii. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e., lye and solids by three technological processes, i.e., mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics. Liquid form can be converted into solid and solid form can be reconverted in liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable. The imports are predominantly in lye form with very small quantity of imports in flake form. However, both the forms are clearly substitutable and like articles. Therefore, the Authority has included all forms of caustic soda (both lye and flakes in the product under consideration.
- iii. Caustic soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classifications, the product is classified under the Customs Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- iv. There is no difference in Caustic Soda produced by the Indian industry and the product exported from the subject country. Caustic Soda produced by the Indian industry and imported from the subject country is comparable in essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. Caustic Soda produced by the Domestic Industry should be treated as like article to the Caustic Soda imported from the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules.

Views of the opposing interested parties

4. None of the importers, consumers, exporters and any other interested party has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, and like articles.

Examination by the Authority

5. The Authority notes that there is no significant difference in subject goods produced by the Indian industry and imported from subject countries. Even though the product is produced through different process, the subject goods produced by the Indian industry and that imported from subject countries are comparable in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as like articles to the subject goods imported from subject countries in accordance with the anti-dumping Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**Views of the Domestic Industry**

6. Following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to scope and standing of the Domestic Industry:
 - i. The applicants have argued that the Domestic Industry's position has been clearly stated in the Initiation Notification that the present petition has been filed on behalf of Indian producers of the subject goods by AMAI. 4 major producers of the subject goods i.e., M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., M/s DCW Ltd., M/s Grasim Industries Ltd, M/s SIEL, have furnished the necessary costing and financial information for analysis.
 - ii. None of the participating (petitioner) companies has imported the product nor are they related to any importer/exporter of the product under consideration from the subject countries. The production of the petitioner companies constitutes a major proportion in the Indian production. The participating companies therefore, have satisfied the requirement of standing and constitute Domestic Industry within the meaning of the Anti-dumping Rules.

Views of the opposing interested parties

7. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to standing and scope of Domestic Industry:
 - i. There appears to be certain lack of clarity with regard to the exact standing and composition of the Domestic Industry. While it is clear that the petition was filed by AMAI on behalf of producers, it is not clear which companies are presently being examined in terms of injury and Domestic Industry parameters. In absence of any update it is assumed that there has been no change in the Domestic Industry participants since the filing of the Petition and the Domestic Industry therefore consists of GACL, DCW, Grasim and SIEL.
 - ii. The Petitioners are involved in import of the product under consideration. As indicated by GACL's Annual Report in which they have explicitly stated that they had imported approximately *** MT of Caustic Soda Lye and traded the same to domestic consumers during the period 2015-16 (POI).
 - iii. The fact that only 10 out of 34 producers is supporting the petition shows that rest of the industry does not see imports from Japan as a threat; and these producers have been able to increase their total share in total domestic production and consumption

Examination by the Authority

8. The application for the investigation was filed by the Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), on behalf of the domestic producers of caustic soda. Initially 4 producers of the subject goods, i.e., M/s DCW Ltd, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., M/s Grasim Industries Ltd., and SIEL, commanding about 47.70% of domestic production of the subject goods participated as domestic producers for the purpose of injury investigation against alleged dumping from Japan and Qatar.
9. The petitioner companies have declared that they are not related either to any exporter or producer in the subject country or any importer of the subject goods in India of the PUC.
10. Interested parties have argued that one of the petitioner companies M/s GACL who has imported subject goods in the Period of Investigation, should be treated as ineligible in terms of Rule 2 (b). Examination of the facts has revealed that an insignificant quantity of imports were made but from China PR and Iran, who are not Subject Countries. It is thus considered appropriate to consider GACL as an eligible domestic producer in terms of AD Rules.
11. As regards the submission that only 10 out of 34 producers have submitted the application, the Authority notes that the petitioner has been filed by AMAI which is an association representing all the 34 domestic

producers, out of which 10 producers have expressly supported the application and have provided data. This does not tantamount to mean that other producers are opposing the application. The production by the petitioner companies constitutes a “major proportion” of total Indian production.

12. After careful examination of the legal provisions and facts of the case, the Authority considers that the applicant is an eligible Domestic Industry in terms of Rule 2 (b) for both subject countries i.e. Japan and for Qatar. The production of the applicant accounts for major proportion of Indian production of the like article. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes eligible Domestic Industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. MISCELLANEOUS ISSUES

Views of the Domestic Industry

13. The submissions of Domestic Industry are summarized as follows:
 - i. The interested parties have changed their stance regarding withdrawal of petition against Japan, they raised the issue which the petitioner acknowledged and hence withdrew the petition against Japan. As regards to sunset review investigation, that issue is beyond the scope of the present investigations.
 - ii. The withdrawal of the application against Japan will not affect the position of petition in relation to Qatar. The application filed by the petitioner had separate information on Japan as well as Qatar. Terminating investigation against one of the subject countries cannot render the initiation invalid. The facts before the Authority at the time of initiation and at the stage of final findings can undergo change. No prejudice is caused to any party since the interested parties have been provided with information of both the countries separately and they have sufficient time to offer comment on injury to the Domestic Industry on account of Qatar itself. In some investigation, the Designated Authority may find some imports as undumped and exclude the same for injury analysis. The same however does not vitiate the initiation or investigation or determination.
 - iii. Neither Domestic Industry nor interested parties were given an opportunity to offer their views on proposed rejection, nor is the decision to reject the withdrawal consistent with the law. It is quite unclear whether the Designated Authority can accept or reject a submission/request without providing opportunity to interested parties and without issuing a show cause to the petitioner/Domestic Industry.
 - iv. Rule 14 has used the term “shall” and “immediately”, the said rule has laid no time frame within which the Domestic Industry can withdraw the petition. In fact, the petitions are routinely withdrawn after issuance of disclosure statement in Europe. Similarly, US law provides that a review request can be withdrawn by the petitioner after an exporter has filed questionnaire response, thus it cannot be said that a withdrawal of petition post oral hearing is belated stage. It cannot also be said that the oral hearing held is at a belated stage.
 - v. Multiple countries dumping the subject goods are on account of global demand supply gap and in fact shows that the state of the Domestic Industry is vulnerable to dumping. Further, the respondent should limit its arguments to facts and not conjecture. It need to specify what other factors are causing injury to the Domestic Industry and even assuming that there are other factors other than dumped imports it must be shown that the factor is such which breaks the causal link between dumping from subject country and injury caused to the Domestic Industry.

Views of the opposing interested parties

14. The interested parties have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination adopted by the Domestic Industry in its petition and their injury claims. While the issues regarding dumping and injury determination have been dealt in the appropriate

places in this finding, the general issues raised by the parties to the investigation have been examined hereunder to the extent they are relevant. For the sake of brevity, the submissions of the parties and issues raised therein have been summarized as follows:

- i. One set of exporters demanded that the present investigation against Japan should be terminated as the Domestic Industry has withdrawn its application vide its letter dated 24th August, 2017 in respect of imports from Japan in terms of Rule 14 of Anti-dumping Rules.
- ii. Second set of exporters stated that withdrawal should not be allowed and that withdrawal has been made because Domestic Industry is fearful of negative dumping and negative injury.
- iii. Further, the sunset review initiation against Japan should not be initiated since fresh anti-dumping investigation was initiated on the imports of caustic soda from Japan based on application filed by the Domestic Industry and also keeping in view that in the MTR investigation against the imports of USA, Iran and Saudi Arabia, the Authority categorically note the exclusion of Japan as the country attracted “Nil” rate of duty in the earlier investigation. Thus it is clear that the DI as well as the Authority was of the opinion that there is no existing duty on Japan, now opposite stand cannot be taken by initiating review investigation against Japan.
- iv. DCW has withdrawn its application and support to the present investigation on imports from Qatar vide letter dated 14th December, 2016. Thus, Domestic Industry standing must be clarified. If there has been a change in the domestic producers that support the Petition, fresh data in the formats of Proforma IV-A and IV-B must be provided. Since a change in the Domestic Industry composition could potentially change the entire injury analysis, any such change must also be accompanied by a fresh hearing being held to allow the interested parties sufficient opportunity to defend their interests.
- v. The Petitioners have also included the landed price in US dollars, which is clearly not the currency in which any of the Indian buyers operate, it has done to demonstrate reduction in price.
- vi. The Petitioners have failed to provide sufficient information, or have provided inconsistent information and data with respect to Import of the product under consideration by Petitioners, Price Undercutting, and Injury Data.
- vii. With the removal of Japan from the scope of the investigation, the entire initiation is now rendered in fructuous since there was never an independent assessment conducted for Qatar at the time of initiation.

Examination by the Authority

15. The miscellaneous submissions have been examined as under:

- i. Rule 14(a) of the Rules, 1995 states that:

Termination of Investigation: The Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if-

(a) It receives in writing for doing so from or on behalf of the Domestic Industry affected, at whose instance the investigation was initiated;

- ii. Here, plain reading of the rule, demonstrates that the Domestic Industry as a whole can request for termination of a particular investigation after the initiation of the investigation. However, in the present case, Association had filed a petition on behalf of 4 petitioner companies, who were declared as “Domestic Industry” as per Rule 2(b) and 5(3) of the Rules, by the Authority for initiating investigation against two countries. Subsequently, the Association requested for

withdrawal of application against one of the subject country viz. Japan, but continue against the other country viz. Qatar. After that one of the petitioner company informed that they would like to withdraw the application against one of subject country viz. Qatar. It appears that these requests are being made without application of mind. After the initiation of the investigation it cannot be left to the whims and fancies of the applicant/s to pick and choose the investigating countries against which the investigation needs to be continued or terminated. Thus the withdrawal request by AMAI against Japan is considered as null and void. The Authority has decided to proceed with the investigation and conclude it on the basis of information available and verified to the extent possible.

- iii. As regards the issue of withdrawal of application by DCW against Qatar, the Authority notes that after the initiation of the anti-dumping investigation against multiple countries, the petitioner cannot start to behave erratically or be selective and choose to withdraw the application or support against a particular subject country which it had originally supported. They may decide to apply for termination of entire proceedings by withdrawing the whole application hence making their withdrawal look more credible rather than being selective and making their withdrawal look whimsical and biased. Standing of a petitioner is a basic requirement of any anti-dumping investigation, and they cannot get off the wagon midway. If any petitioner wants to withdraw the application, then as per Rule 14(a) of the Rules, the whole application needs to be withdrawn.
- iv. As regards the contention of the exporters that the present investigation against Japan should be terminated pursuant to the withdrawal of investigation against Japan by the Domestic Industry, the Authority observes that this contention is not correct as explained in para above. In any case, the Authority has already communicated its stand vide letter dated 1st September, 2017 that the termination of investigation against Japan at such belated stage of the investigation is unwarranted. The letter has been kept in the public file for inspection by all the interested parties in accordance with rule 6(7).
- v. As regards the contention regarding exclusion of Japan from the review investigation conducted separately by the Authority, the same has already been made clear by notifying SSR initiation notification 7/16/2017-DGAD dated 20th November, 2017 against Saudi Arabia and USA only.
- vi. As regards the contention that the petition filed by the Domestic Industry is based on incorrect data, the Authority observes that the assertion so made is not substantiated. In any case, it may be mentioned that the Authority had initiated the investigations after being fully satisfied about the evidence presented by the Domestic Industry was sufficient to justify the initiation of the investigation. The Authority also satisfied itself about the accuracy and the adequacy of the data/information which was necessary to initiate investigations in terms of Rule 5. Therefore, the Authority does not find any merit in the submission made by the interested parties.
- vii. As regards the issue of usage of US dollars, the Authority is of the view that landed price in US Dollars is in accordance with standard practice. US Dollar as a unit of measurement because it is universally accepted currency. There is no unfair advantage to the petitioner on account of such conversion. The Authority has relied upon DGCI&S data for the analysis.
- viii.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

Views of the Domestic Industry

16. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

- i. No submissions have been made by the Domestic Industry regarding Confidentiality.

Views of the opposing interested parties

17. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to consolidated injury data. The Petitioner has claimed excessive confidentiality over the IHS Chemical report that has been relied upon for computing the normal value for Japan
 - ii. The Petitioners have failed to observe the requirements regarding the treatment of confidential data.
 - iii. The Petitioners have provided no non-confidential summaries of essential data contained in the Petition, in particular with respect to costs of the Domestic Industry or the calculation of the normal value (Annexures 3.1A and 3.1B of the Petition), without justifying the impossibility of summarizing these data.
 - iv. The Petitioners failed to disclose the sources of most of the data contained in the Petition without any justification. The non-disclosure of sources also violates confidential treatment provisions. This also casts additional doubt on the accuracy of the data supporting the Petition. If the Petitioners had sufficient evidence of the existence of dumping, injury and causal link, they would have disclosed this evidence in the non-confidential version of the Application.

Examination by the Authority

18. The Authority made available non confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

19. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

“Confidential information”

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the Designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the Designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The Designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the Designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

20. The WTO Agreement on Anti-Dumping provides as follows with regard to confidentiality of information-

“Article-6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

Article-6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

Article-6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.

Footnote to Article 6.5.2 (footnote 18 of the WTO Agreement on Anti-Dumping) provides as follows:- Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected."

21. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the justification of their claims and the specific provisions of law as interpreted by the Hon'ble Supreme Court. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

22. The Provisions pertaining to normal value are given in Section 9A(1)(c) of the Act and Annexure-I to AD Rules.
23. The Authority examined the details of total domestic sales of the subject goods by the producers/exporters in the subject countries and the fact that they were representative when compared to the exports of the subject goods to India. It was examined whether the sales are under ordinary course of trade in terms of Para 2 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. Wherever the producers/exporters have provided transaction wise details of sales made in home market and same have been accepted by the Authority, the said information has been relied upon to determine the normal value of the subject goods sold in the home market.
24. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers from the subject countries have filed the prescribed questionnaire responses along with their exporters.
- ix. M/S. Asahi Glass Co., Ltd, Japan
 - x. M/s Tosoh Corporation, Japan
 - xi. M/s Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Japan
 - xii. M/s Mitsui & Co., Ltd., Japan
 - xiii. M/s Qatar Vinyl Company (QVC), Qatar
 - xiv. M/s Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat)Q.J.S.C., Qatar
 - xv. M/s Tricon Overseas Inc, Panama
 - xvi. M/s Hiranyavarnaam Chemicals & Alkalies Pte Ltd, Singapore

Views of the Domestic Industry

25. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

- i. Normal Value in case of Japan has been determined as per the rates of Caustic Soda published in IHS Chemical (Global Chlor-Alkali) monthly publication and Authority is requested to adopt the same.
- ii. The average (of Lye and Flake) import price has been determined for the purpose of determination of volume and value of imports. The normal value and NEP has been determined at ex-factory level after being adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Expenses
- iii. The dumping margin is not only above de minimis but also quite significant and Domestic Industry has suffered material injury as a result of dumping.
- iv. In absence of any evidence of prices of the product under consideration in the domestic market of the Qatar, at the time of initiation, the normal value has been constructed for all exporters/producers from Qatar on (a) Consumption factor of raw materials, utility and all other costs have been adopted on the basis of information/data of efficient producer of the Domestic Industry (b) Power rate for Qatar has been taken as per rate available at Qatar General Electricity & Water Corporation and (c) Profit has been taken @ 5% of ex-factory cost excluding interest.
- v. It is a well-established principle that quantity and quality of evidence improves as an investigation progresses. Information sufficient for the purpose of initiation may not be sufficient for the purpose of determination. At the same time, information required for determination need not be insisted upon at the time of initiation.

Views of the opposing interested parties

26. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The Petitioners have failed to arrive at the export price in the present investigation in the manner prescribed under the law and have thus failed to establish the existence of dumping as required under Article 5.2(iii) of the Anti-Dumping Agreement: For calculating the dumping margin in case of Japan, third country exports from Japan are also considered. The construction of the export price is not allowed in any of the provisions of the AD Agreement.
- ii. The Petitioners have chosen the Indian Industry prices from raw materials and power consumption and adopted international prices for power rates for the construction of the cost in Qatar. The Petitioners have themselves admitted in their Annual Reports the high cost of production in India. Therefore, Petitioners have tried to artificially inflate the dumping margin by attributing the Domestic Industry's high cost of production to Qatar. The normal value and export price filed by the cooperating producers/exporters may be used to determine dumping margin
- iii. The Petitioners have not fulfilled their obligation to provide accurate and verifiable data on normal value at the time of initiation. At the time of initiation, the onus of proof lies squarely and solely on the Petitioner to prove that the allegations made against the subject countries were credible with respect to the calculated normal value. Merely because co-operating parties from the subject countries have provided their data for calculating the normal value, the Petitioners are not absolved of their obligation

Examination by the Authority

27. The applicant had submitted evidence at the time of filing the application on the basis of DGCI&S data for imports and IHS Chemical publication data for calculation of normal value. The Authority examined the accuracy and adequacy of the evidence furnished in the application and prima facie concluded that there is sufficient evidence regarding dumping, injury and causal link for initiation of

the subject investigations in accordance with the Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from Japan and Qatar.

28. The Authority notified all the interested parties and invited them to file response to enable the Authority to examine the facts/data and arrive at comprehensive conclusion. The specific responses from interested parties definitely improves the quantity and quality of evidence as investigation progresses.
29. The Authority has examined the questionnaire responses from the co-operative producers/exporters and after due verification and appropriate adjustments, the normal value and net-export price at ex-factory level and consequent dumping margin has been determined.

I. JAPAN

30. The Authority noted that three producers namely, M/S. Asahi Glass Co., M/s Tosoh Corporation and M/s Shin-Etsu Chemical Co., Ltd have filed the exporter questionnaire responses. The producers have exported the subject goods to India through unrelated exporter M/s Mitsui & Co., Ltd. The questionnaire responses are complete and accepted after due verification in a table study.

a. M/s Asahi Glass Co., Ltd through Mitsui & Co., Ltd.

Normal Value

31. During the POI, M/s Asahi Glass has sold subject goods in the domestic market to related and unrelated parties. It is noted that majority of the domestic sales have been made to non-affiliated parties during the POI. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. As profitable sales of M/s Asahi Glass were less than 80% of the total domestic sales, the Authority has considered only profitable domestic sales transactions for determination of the normal value. M/s Asahi Glass has claimed adjustment on account of inland freight and credit expense which Authority has accepted. Accordingly, normal value at ex-factory level for Asahi Glass has been determined for subject goods and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

32. During the POI M/s Asahi Glass Co., Ltd has exported the subject goods to India through M/s Mitsui & Co., Ltd. The sales to Mitsui & Co., Ltd are on FOB basis. The producer claimed adjustment of inland freight, surveyor fees and credit expense, and the same have been accepted after necessary verification of documents. The net ex-factory export price for the producer is as mentioned in table below.

Producer	Exporter	NV USD/MT	NEP USD/MT	Dumping Margin		
				USD/MT	%	Range
M/s Asahi Glass Co., Ltd	M/s Mitsui & Co., Ltd	***	***	***	***	1-10

b. Tosoh Corporation (producer) through its exporter M/s Mitsui & Co., Ltd

Normal Value

33. From the responses filed by M/s Tosoh Corporation, the Authority notes that it is a producer of the subject goods. In the domestic market, the Company sells the subject goods to both related and unrelated end-users. The questionnaire response filed by the producer/exporter was examined for domestic sales. The same was re-examined and the ordinary course of trade test was reapplied and it is found that more

than 80% transactions of the total domestic sales are profit making. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based on all the sales transactions. The Company has claimed adjustments on account of price adjustments, inland freight, surveyor cost, storage cost, handling cost; insurance cost and credit cost. The Normal value of the producer determined is mentioned in the table below.

Export Price

34. During the POI, M/s Tosoh Corporation., Ltd has exported the subject goods to India through M/s Mitsui & Co., Ltd. The sales to Mitsui & Co. Ltd are on FOB basis. The exporter claimed adjustment on account of overseas freight, clearance & handling charges, overseas insurance, brokerage and credit expense, and the same have been accepted after necessary verification of documents. The adjustments were also claimed by the producer on their exports are on account of price adjustments, inland freight, surveyor cost, storage cost, handling cost, insurance cost, others and credit cost. The Authority has not accepted the adjustment claimed under the heading “others” from the export price. The export price for the producer is as mentioned in table below.

Producer	Exporter	NV USD/MT	NEP USD/MT	Dumping Margin		
				USD/MT	%	Range
M/s Tosoh Corporation	M/s Mitsui & Co., Ltd	***	***	***	***	0-5

c. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. through its exporter M/s Mitsui & Co., Ltd

Normal value

35. The questionnaire response filed by the producer/exporter has been examined for domestic sales and it is found that more than 80% transactions of the total domestic sales are profit making. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based on complete sales data. They have claimed adjustment on account of quantity adjustments, inland freight, inland insurance, storage cost, handling cost, credit cost and other costs. The Normal value of the Producer determined is mentioned in the table below.

Export price

36. During the POI, M/s Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Ltd has exported the subject goods to India through M/s Mitsui & Co., Ltd. The sales to Mitsui & Co., Ltd are on FOB basis. The producer claimed adjustment of loading cost, clearance & surveyor fees and credit expense. It was also noted by the Authority that the producer has not claimed adjustment of inland freight (which is applicable for FOB transactions). Therefore, Authority has made appropriate adjustment for inland freight from the export price of the producer. The net ex-factory export price for the producer is as mentioned in table below.

Producer	Exporter	NV USD/MT	NEP USD/MT	Dumping Margin		
				USD/MT	%	Range
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	M/s Mitsui & Co., Ltd	***	***	***	***	1-10

II. QATAR

37. The Producer M/s. Qatar Vinyl Company Limited Q.S.C. ('QVC'), has filed a detailed response along with its related exporter Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. Further, two unrelated exporters namely, Hiranyavarnaam Chemicals & Alkalis Pte Ltd, Singapore and M/s Tricon Overseas Inc., Panama, have also filed their detailed responses. The Authority has examined the responses filed and all the relevant appendices.

M/s Qatar Vinyl Company Limited Q.S.C. and M/s Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C

Normal value

38. The response filed by producer and exporter was examined. The Authority notes that QVC is the sole producer of caustic soda in Qatar. The major quantity of domestic sales is through a related trader i.e. Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. and a small quantity of sales is direct. A majority of domestic sales are made to affiliated end-users. QVC has submitted that the domestic market is peculiar and the prevailing domestic sales prices are not reflective of the global market condition as they are uncharacteristically inflated on account of certain special commercial considerations between QVC and its customers. As a result, QVC has submitted that normal value ought not to be calculated on the basis of domestic sales reported under Appendix 1.

39. The Authority examined the appendix 1 data provided by QVC and noted that the sales in the domestic market are made in the ordinary course of trade with significant profit margins. It is therefore decided to accept the domestic selling prices for normal value calculation after accepting due adjustments. The normal value determined is as mentioned in the table below

Export price

40. QVC exports goods to India only through Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. Muntajat's export sales to India are made directly to customers in India and as well as through unrelated exporters namely M/s. Hiranyavarnaam Chemicals & Alkalis Pte Ltd, Singapore and M/s Tricon Overseas Inc., Panama.

41. For its direct sales to India, Muntajat has claimed adjustments on account of overseas freight, clearance & handling charges, overseas insurance, brokerage and credit expense, and the same have been accepted after necessary verification of documents. The export price determined is as mentioned in table below.

42. M/s. Hiranyavarnaam Chemicals & Alkalis Pte Ltd, Singapore has filed exporters' questionnaire response. They have given details in appendix-2 and the adjustments claimed by Hiranyavarnaam on their exports are on account of credit cost and bank charges. The export price for the exporters is as mentioned in table below.

43. M/s Tricon Overseas Inc, Panama has filed exporters questionnaire response. They have given details in appendix-2 and the adjustments claimed by Tricon on their exports are on account of commissions, courier fees, discount interest expense, interest expense, export LC fees and ocean cargo insurance. The export price for the exporters is as mentioned in table below.

Producer	Exporter	NV	NEP	Dumping Margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
Qatar Vinyl Company Limited Q.S.C.	Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C	***	***	***	***	110-120

Qatar Vinyl Company Limited Q.S.C.	Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. and Hiranyavarnaam Chemicals & Alkalies Pte Ltd	***	***	***	***	110-120
Qatar Vinyl Company Limited Q.S.C.	Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. and M/s Tricon Overseas Inc	***	***	***	***	110-120

44. It is seen that the dumping margin is significantly positive for producer/exporter from Qatar. Whereas, the dumping margin for producers/exporters from Japan namely M/s Tosoh Corporation the dumping margin is below de minimus and for M/s Asahi Glass Co., Ltd and M/s Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. the dumping margin is positive and above de minimus.

G. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the Domestic Industry

45. The following are the injury related submissions made by the Domestic Industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- The volume of imports from each of the subject countries is significant. It has increased by 76% in the POI as compared to the base year in case of Qatar. The volume of dumped imports from Qatar has increased significantly over the injury period as well as in relation to production and consumption. Imports from Japan were negligible in the base year and then increased in 2013-14, imports from Japan witnessed huge surge in the POI.
 - The demand for the product under consideration has increased throughout the injury period.
 - The imports from Japan as well as Qatar are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market. Presence of dumped imports from Qatar and Japan have gained market share in India, while Domestic Industry market share has declined.
 - Price undercutting should be determined only considering those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the Domestic Industry. Petitioner has also calculated price undercutting considering only those transactions that were, in fact, undercutting the prices of the Domestic Industry.
 - The imports are resulting in suppression of the prices in the market, the cost of production increased, selling price has declined in 2013-14 and then increased marginally upto POI. Also import price from Japan has declined over the period and import price from Qatar declined over the injury period with marginal increase in POI as compared to the previous year. Thus, dumped imports from Qatar and Japan has prevented price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.
 - The capacity has increased over the injury period. Production volumes have also increased throughout the injury period. The capacity utilization has also increased. However, sales of the Domestic Industry have not increased in proportion and to the extent of increase in production. Sales have, in fact declined as compared to 2013-14. Resultantly, the level of inventories has remained significant.

- vii. The market share of the Domestic Industry has increased in 2013-14 and then declined upto POI when compared with previous year and base years and that of dumped imports from Qatar have increased with some decline in the POI as compared to the previous year. Market share of Japan has increased significantly in the POI. Market share of Japan and Qatar collectively has increased significantly.
- viii. Employment and wages paid have increased over the injury period. Productivity of the Domestic Industry has moved in tandem with production
- ix. Despite of positive growth in respect of Production, the Domestic Industry suffered negative growth in respect of sales, market share, profits, return on investment and cash flow. Cost of sales increased over the injury period. However, selling prices have declined in 2013-14 and then increased marginally upto POI. But increase in selling price thus, the Domestic Industry had negative growth in both cost of production and selling price. The negative growth in selling price is due to dumping.
- x. Growth of the Domestic Industry has become negative in terms of sales, market share, inventories, profits, ROI.
- xi. The imports are available at prices lower than the selling price of the Domestic Industry. Consequently, the consumers are increasingly switching over to imports.
- xii. Imports from Qatar and Japan are at dumped prices and are undercutting domestic selling prices and causing price depression. Resultantly, profitability of the Domestic Industry has declined. Margin of undercutting and injury margin is significant.
- xiii. The imports of product under consideration from other countries are either already attracting ADD or are low in volume, demand has increased, there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration and there is no trade restrictive practice which could have contributed to injury to the Domestic Industry. Performance of other products being produced and sold by the petitioner is not a possible cause of injury to the Domestic Industry and injury in export operations has not been attributed to domestic operations. The technology has also the production process for producing subject goods has not undergone any significant development.
- xiv. There is no de minimus level in relation to demand. The law recognizes the potential adverse effect that's country can have if its share is more than 3% in imports. In the instant case imports from Qatar is 11.68% which is significant.
- xv. It is not the prerogative of the Designated Authority to concern itself with the ability of the Domestic Industry to meet the domestic demand for subject goods as the imposition of Anti-dumping duty on the product under consideration does not restrict the entry of the goods in the Indian market, it just provides a level playing field to the imported goods and domestic like article.
- xvi. The Domestic Industry bases its selling price on cost as well as landed price of imports. In the present situation when there are presence of dumped imports from various other sources as well, the profitability cannot be solely linked to one subject country. The fact that the imports are undercutting the prices of the Domestic Industry shows adverse effect of import price on the Domestic Industry.
- xvii. Assuming that the average injury margin would be low, the petitioner requests the Authority to consider only those transactions that are below non injurious price for calculation of injury margin. Reference is made to WTO Report in the matter of European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil wherein the panel held that transactions with positive undercutting needs to be worked out to evaluate price undercutting effect. Reference is also made to the Hon'ble Tribunal's order in the matter of Kothari Sugars & Chemicals Limited *versus* Designated Authority which allowed considering transactions above NIP to calculate injury margin.

- xviii. EC determines two margins for injury, i.e., price undercutting and price underselling. Methodology that is applicable to calculation of one margin, i.e., price undercutting cannot be said to be non-applicable on other, i.e. price underselling. Infact, the fact that anti-dumping measures gets applied on the basis of price undercutting margin in EU further strengthens the argument that there is no bar in considering only injurious transactions to determine injury margin. Above all, while price undercutting shows the extent to which the imports were undercutting (and caused injury), injury margin shows the extent the imports are likely to remain injurious. If the argument of the interested parties is accepted that negative price undercutting transactions can be eliminated for price undercutting, but not for injury margin, it shall imply that there can be situation where the price undercutting is more than injury margin. Such situation may be found even in those cases where the industry is suffering losses. Thus, if negative undercutting transactions are to be excluded for price undercutting purposes, the same must be excluded for injury margin purposes as well.
- xix. The assertion that the alumina industry being a major industrial consumer located in eastern part of India inflates the transport price of product under consideration is preposterous solely on the ground that even though major producers are located in west coast, the producers of Caustic Soda are spread throughout the country. Producers in the east have production capacity *** Lakh Metric Ton; hence the Alumina industry can easily get its demand fulfilled without incurring higher transportation cost.

Views of the opposing interested parties

46. The following are the injury related submissions made by the opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority :
- i. The Petitioners at the second public hearing have admitted that there is a negative injury margin in the present investigation, thus no duty can be applied in the present investigation.
 - ii. The *zeroing* methodology as suggested by the Petitioner has been repeatedly held to be inconsistent with the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“**AD Agreement**”) while calculating the dumping margin in a number of Panel and Appellate body reports. based on the WTO report, the zeroing methodology that has been proposed by the Petitioner is not only devoid of any logic but is also arbitrary and inconsistent with the WTO findings with respect to zeroing. The Hon'ble Designated Authority should therefore include all the transactions of subject goods from the subject countries taken place during the POI to compute the injury margin rather than only selective few which would be extremely arbitrary and prejudicial against the exporters. The Hon'ble Designated Authority is requested to find that the new methodology proposed by the Petitioner cannot be upheld and is in violation to the WTO findings with respect to zeroing.
 - iii. There is no injury caused to the DI from subject imports from Qatar.
 - iv. The management of one of the Petitioners has cited high cost of production, purchase of new elements and imports from China and Iran as the difficulties faced by company in their Annual Report. While one other Petitioner has admitted that the Anti-Dumping duties that are currently imposed are sufficient to allow sustainable operation.
 - v. There is no volume effect of the subject imports since the total imports from Japan as compared to total demand in the market is negligible and does not exceed 3%. Market share of the subject countries in total demand is also insignificant and does not exceed 5% throughout the POI.
 - vi. There is no price effect of the alleged dumped imports since the landed price of the product under consideration has no impact on the selling price of the Petitioners. The landed value of the subject goods from Japan would also be in the same range as in caustic soda from Chinese Taipei, where the Authority has determined that there was no price underselling. The NIP of the Domestic Industry would remain same as in case of Taipei since the constituent of the Domestic Industry is same, thus

the negative price underselling determined for Taipei will not change to a positive price underselling determination for Japan.

- vii. If the selling price and thus profit made by the Petitioners was dependent on price undercutting, the Petitioners should have made higher profits in 2013-14 compared to the base year when price undercutting was the highest.
- viii. It is a well-established practice that price undercutting and underselling are both calculated using Indian Rupees as the currency rather than dollars. The landed price has remained stable over the period of injury, even though there has been a substantial fluctuation in the exchange rate. However, in order to demonstrate an imagined reduction in price, the Petitioners have also included the landed price in US dollars, which is clearly not the currency in which any of the Indian buyers operate.
- ix. Domestic Industry is experiencing positive growth in most of the economic parameters i.e. production and sales, instalment of new production capacity every year, employment and productivity per head, profitability.
- x. In absence of price effect, volume effect and negative economic parameters, there cannot be material injury to the Domestic Industry. The main periods of decline in terms of injury parameters were prior to the period of investigation at a time when the Petitioners are not alleging the existence of dumping, and there has indeed been an improvement in parameters since then.
- xi. There is no threat of injury to the Domestic Industry. There cannot be simultaneous claims or determination of material injury as well as threat of material injury since claim of threat of material injury itself implies that there is no present material injury and vice versa. WTO panel and European Courts interpreted that the economic factors are all positive and on whole painted a picture of an industry in a situation of strength not of fragility or vulnerability, thus the claims of threat of injury must be rejected as per the interpretation by WTO panel and European Courts.
- xii. The Domestic Industry is operating at full capacity and is not able to cope with the growing demand. The unutilised production capacity of ***% is negligible and absolutely normal for such industry to carry out the necessary maintenance operations.
- xiii. The caustic soda industry is growing in India due to steady increase in demand. The company intends ***% capacity expansion of the caustic soda plant, the annual report also demonstrates that Indian caustic soda industry is experiencing positive growth for caustic soda which will continue in the coming years, also the other Indian producers not supporting the petition are experiencing positive performance, thus the Domestic Industry cannot suffer any injury.
- xiv. Injury, if any, is caused by the imports originating in other countries since despite of hefty ADD against 8 countries, imports have increased during the POI, while imports from countries not attracting AD have come down by 60% to reach a low level of 5,757 MT.
- xv. There is no causal link between dumping and the alleged injury. The Petitioner continues to be injured even after thirteen years of duty on almost all sources of caustic soda, it is obvious that the injury has nothing to do with allegedly dumped imports, but is rather a result of other extraneous factors such as the performance of chlorine. The Petitioners are falsely accusing the subject countries for the injury suffered by them.
- xvi. There is no correlation between the losses suffered by the DI and the imports from Japan. The DI reported its worst profits in 2014-15 when imports in Japan were Nil.
- xvii. The DI suffers from structural problems. India has 34 companies out of which only 10 are petitioners rest of the producers managed to increase their market share, which clearly demonstrates that the majority of Indian producers of caustic soda do not see imports from Japan as threatening their business.

- xviii. There is a huge demand supply gap of about 1 million tonnes per annum, therefore, the users of PUC are left with no other option but to fulfil the gap by resorting to imports.
- xix. Demand fulfilled by import from Japan is very insignificant and accounts for only 2.5% of total demand.
- xx. The transportation of caustic soda from the west coast to the east coast of India causes unnecessary hardships and increase in the cost of raw materials to the alumina manufacturers. This results in the demand of caustic soda from other countries having lower cost of transportation along with supply of voluminous quantity leading to lower cost of raw materials (caustic soda) for the alumina industry. This, in turn, results in increase in demand from all viable sources, also due to the domestic producers' inability to supply in the lot sizes required by the alumina users.

Examination by the Authority

47. The impact of the dumped imports on the Domestic Industry is to be examine in terms of Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules, which states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

48. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties during the course of the present investigations and considered relevant by the Authority.
49. For the examination of the impact of imports on the Domestic Industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra. The Authority computed the non-injurious price in accordance with Annexure 3 to the Anti-dumping Rules and the established practices of the DGAD.

I. Assessment of Demand

50. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the applicant and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	9,69,113	10,38,253	9,88,766	10,11,106
2	Sales of Other Producers	MT	15,58,513	15,79,744	18,25,113	18,54,952
3	Subject Countries	MT	31,591	68,120	57,003	1,54,768
(i)	Japan	MT	42	36,248	-	99,302
(ii)	Qatar	MT	31,549	31,872	57,003	55,466
4	Countries Attracting ADD	MT	2,57,624	2,34,759	3,33,855	3,14,362
5	Other Countries	MT	14,272	1,595	15,799	5,757
6	Demand/Consumption	MT	28,31,112	29,22,472	32,20,537	33,40,945

51. The Authority notes that the demand for the product under consideration has consistently increased over the entire injury period. The share of Indian producers in total domestic demand is 86% and market share of imports from subject countries is 4.6%. Another 9.4% share of domestic demand of subject goods is being imported from those countries against which antidumping duty is already in force.

II. Volume Effect of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

52. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries has been analyzed for 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI as under:

SN	Imports	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Total Imports	MT	3,03,486	3,04,474	4,06,657	4,74,887
2	Subject Countries	MT	31,591	68,120	57,003	1,54,768
(i)	Japan	MT	42	36,248	0	99,302
(ii)	Qatar	MT	31,549	31,872	57,003	55,466
3	Countries Attracting ADD	MT	2,57,624	2,34,759	3,33,855	3,14,362
4	Other Countries	MT	14,272	1,595	15,799	5,757
Market Share in Imports						
1	Subject Countries	%	10	22	14	33
(i)	Japan	%	0	12	0	21
(ii)	Qatar	%	10	10	14	12
2	Countries Attracting ADD	%	85	77	82	66
3	Other Countries	%	5	1	4	1
4	Total	%	100	100	100	100
Imports in relation to						
1	- Production	%	2.93	5.95	4.57	11.62
2	- Demand	%	1.12	2.33	1.77	4.63

53. It is noted from the above table that imports of the subject goods from Japan have increased significantly in absolute terms in POI. Imports have gone up from zero in base year to 21% during POI. The imports from Qatar have shown a decline when compared to the previous year, while there is an increase when compared to the base year.

III. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

54. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price

increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with the landed cost of imports from subject countries.

a. Price Undercutting

55. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the Domestic Industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the Domestic Industry were determined at the ex-factory level.

SN	Particulars	Unit	Japan	Qatar
1	Landed price of imports	Rs/MT	24,955	24,944
2	Net Selling Price	Rs/MT	***	***
3	Price Undercutting	Rs/MT	***	***
4	Price Undercutting (%)	%	***	***
5	Price Undercutting	Range	5-15	5-15

56. It is seen that landed prices of imports (as per DGCI&S) from the subject countries are below the net selling price of the Domestic Industry, resulting in positive price undercutting.

b. Price Underselling

57. The Authority has also examined price underselling suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports from subject countries separately for lye and flakes form. The weighted average non-injurious price estimated for the Domestic Industry has been compared with the landed price of imports from the subject country to examine the underselling effects of the dumped imports as follows

SN	Particulars	Unit	Japan	Qatar
1	Import Volume	MT	99,302	55,466
2	Non-Injurious Price	US\$ Per MT	***	***
3	Landed Price of Imports	US\$ Per MT	24,955	24,944
4	Price Underselling	US\$ Per MT	(***)	(***)
5	Price Underselling	%	(***)	(***)
6	Price Underselling	Range	(5)-5	(5)-5

58. It is noted from the above table that the price underselling effect is negative both for Qatar and Japan indicating that the prices at which the imports from the subject countries are landing in India (as per DGCI&S data) is higher than the non-injurious price of the Domestic Industry.

c. Price Suppression and Depression

59. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Landed Price of Imports	Rs/MT	25,392	25,235	23,721	24,953
2	Trend	Indexed	100	99	93	98
3	Landed Price - Countries attracting ADD	Rs/MT	26,751	25,320	24,672	25,568
4	Trend	Indexed	100	95	92	96
5	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	100	113	112
7	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	92	98	100

60. From the above Table, it is clear that the landed value of imports from the subject countries decreased marginally when compared to the base year. The selling price has remained at the same level when compared to the base year as well as previous year; however, there is a decline during 2013-14. The cost of sales increased during the injury period and especially when compared to base year. Thus, the above data demonstrates that despite the increase in cost of sales, the Domestic Industry is unable to increase the selling price, indicating that the prices of the Domestic Industry are suppressed and depressed. However, it is noted that the selling price is always above the cost of sales throughout the injury period and POI, which indicates that in spite of low value imports, the domestic industry is able to realise a higher selling price.

IV. Economic Parameters of the Domestic Industry

61. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

62. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed herein below:

a. Market share:

63. The details of imports, domestic sales and the market share of the Domestic Industry in total demand in India is as below:

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Total Demand/Consumption	MT	28,31,112	29,22,472	32,20,537	33,40,945
2	Sales of Domestic Industry	MT	9,69,113	10,38,253	9,88,766	10,11,106
3	Sales of Other Producers	MT	15,58,513	15,79,744	18,25,113	18,54,952
4	Subject Countries	MT	31,591	68,120	57,003	1,54,768
5	Share					
5a	Of Domestic Industry	%	34.23	35.53	30.70	30.26
5b	Of Other Producers	%	55.05	54.06	56.67	55.52
5c	Of Subject countries - Imports	%	1.12	2.33	1.77	4.63
(i)	Japan	%	0.00	1.24	-	2.97
(ii)	Qatar	%	1.11	1.09	1.77	1.66

64. The Authority notes that the market share of the Domestic Industry has declined in POI as compared to base year, whereas imports from subject countries have increased. However, the share of other Indian producers in total demand is quite significant hence it is difficult to relate the impact of imports on domestic industry, which is less than 5% of total demand in domestic market.

b. Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

S.No.	Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
1	Installed capacity	MT	1,206,050	1,297,543	1,410,650	1,445,800
2	Production	MT	1,076,792	1,144,178	1,247,463	1,331,558
3	Capacity Utilization	%	89.28	88.18	88.43	92.10
4	Domestic Sales	MT	969,113	1,038,253	988,766	1,011,106

65. From the above information, the Authority notes that the capacity of the Domestic Industry has increased during the injury period and POI keeping in line with the increasing demand in the domestic market. Further, both sales and capacity utilization have also increased during the POI as compared to the base year which could again be on the similar rationale.

c. Inventories:

66. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

S.No.	Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
1	Opening	MT	***	***	***	***
2	Closing	MT	***	***	***	***
3	Average	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	126	127	90

67. It is noted that inventories with the Domestic Industry have declined in POI as compared to base year which could indicate better status for the domestic industry though inventories are not conclusive indicator of the injury to the domestic industry.

d. Profits and actual and potential effects on the cash flow

68. The data relating to profit, cash profits and return on investment is shown in the following table:

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	113	112
3	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	92	98	100
5	Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	63	42	57
7	ROI	%	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	58	41	58
9	Cash profit	Rs lacs	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	79	57	72

69. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of Domestic Industry in terms of profit before tax, cash profit and ROI has declined over the injury period and during POI as compared to the base year.

e. Employment, wages and productivity

70. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

S.No.	Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
1	Employees	Nos.	***	***	***	***
1a	Trend	Indexed	100	105	105	106
2	Productivity per employee	MT	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	101	110	117
3	Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	122	136	151

71. It is noted that there was increase in the number of employees which could be to some extent on account of increase in production capacities and the production of the Domestic Industry. The increase in productivity per employee indicates better efficiencies and increase in wages could be in response to the progressive state of normal market conditions with time.

f. Magnitude of Dumping:

72. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports are entering the domestic market thereby affecting Domestic Industry. The above analysis shows that the dumping margin is significantly positive for producer/exporter from Qatar. Whereas, the dumping margin for producers/exporters from Japan namely M/s Tosoh Corporation the dumping margin is below de

minimus and for M/s Asahi Glass Co., Ltd and M/s Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. the dumping margin is positive and above de minimus.

g. Growth

73. The Domestic Industry has shown positive growth in terms of volume parameters during POI, however growth in terms of price parameters have remained adverse.

h. Ability to raise capital investment

74. The Authority notes that the Domestic Industry enhanced capacities during period of investigation and made fresh investments. The petitioner has stated that due to imports from the subject countries they were unable to tap the full potential of increased capacities. However, it is observed that their capacity utilisation is above 92% and with the present analysis it cannot be concluded that their ability to raise capital investments has been affected.

i. Factors Affecting Domestic Price

75. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. The dumped import prices from subject countries are directly affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market. It is also noted that the landed value of subject goods from subject countries (as per DGCI&S data) are below non-injurious price of the Domestic Industry. Further, landed value from subject countries had suppressed / depressed the prices of the Domestic Industry. The petitioner has further stated that the imports of the product under consideration from countries other than subject countries where there is no ADD, are not injuring the Domestic Industry. Demand for the product is showing an increasing trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the Domestic Industry. The petitioner has claimed that the dumped goods from subject countries are responsible for the depressed and suppressed prices of the Domestic Industry. However, it cannot be directly inferred because the market share of other producers is quite significant and the share of imports is comparatively very small.

V. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

76. Having examined the existence/absence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:
- a) Imports from third countries-The imports of the product under consideration from China PR, Korea RP, Iran, Saudi Arabia & USA are already attracting antidumping duties. The present analysis has been done for imports from the subject countries only.
 - b) Trend in Demand-The demand has increased over the injury period. The change in demand is not causing injury to the Domestic Industry.
 - c) Performance of other products- Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has no impact over the reported performance of the subject product. Further, injury, if any, due to other factors has been segregated by the Petitioner.
 - d) Changes in the pattern of consumption: - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.
 - e) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

- f) Developments in technology: - Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.
- g) Export performance: - The claimed injury to the Domestic Industry is solely on account of domestic operations. The Domestic Industry has made some exports throughout the injury period. However, this factor cannot be said to have caused injury to the Domestic Injury.
- h) Productivity: - The claimed injury to the Domestic Industry is not due to deterioration in productivity of the Domestic Industry.

H. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

77. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

S. No.	Producer	Exporter	Landed value	NIP	Injury Margin		
			USD /MT	USD /MT	USD /MT	%	Range
	Japan						
1	M/s Asahi Glass Co., Ltd	M/s Mitsui & Co., Ltd	***	***	(***)	(***)	(5)-5
2	M/s Tosoh Corporation	M/s Mitsui & Co., Ltd	***	***	***	***	0-5
3	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	M/s Mitsui & Co., Ltd	***	***	***	***	0-5
	Qatar						
4	Qatar Vinyl Company Limited Q.S.C.	Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C	***	***	***	***	0-5
5	Qatar Vinyl Company Limited Q.S.C.	Qatar Chemical And Petrochemical Marketing And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. and trader Hiranyavarnaam Chemicals & Alkalies Pte Ltd	***	***	(***)	(***)	(5)-5
6	Qatar Vinyl Company Limited	Qatar Chemical And Petrochemical Marketing	***	***	(***)	(***)	(10)-(1)

S. No.	Producer	Exporter	Landed value	NIP	Injury Margin		
	Q.S.C.	And Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. and M/s Tricon Overseas Inc					

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

78. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed in relevant paras. However, for the sake of clarity, the submissions by the interested parties are being examined as below:

Submissions made by the Domestic industry

79. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The Authority is requested to disclose the non-confidential version of the verification report of the exporters/producers from subject country to offer meaningful comments on the dumping margin calculated.
- ii. It is submitted that the petitioner did not request the termination of the investigation against Japan. The interested parties had pointed out that the initiation against Japan was bad in law as duties were continuing against Japan at nil rate in a previously concluded investigation. Considering the argument, the petitioners applied for termination of investigation against Japan. The interested parties have changed their stance regarding withdrawal of petition against Japan. However, the Authority has rejected the request.
- iii. It is submitted that the dumping margin determined for Japan is too low as compared to the calculations based on the prices that are published in the IHS Chemical. There does not appear to be any justifiable reason for the difference in the dumping margin calculation done by the petitioner based on IHS Chemical prices and that determined by the Authority based on the responses of the exporters. The responding exporters from Japan represents the major producers of subject goods in Japan, and the prices that are published in the IHS Chemical should ideally represent the prices prevailing in the subject country. Thus, it appears that there is some suppression of facts by the exporters.
- iv. It is submitted that the NIP determined is too low leading to insufficient injury margin.
 - a. Under Annexure-III, only inefficient utilization of raw materials or utilities is required to be normated. Bonafide changes in the raw materials are not required to be changed. Only when the Authority finds that the consumption is a result of inefficient utilization of inputs, that the Authority may normate the same.
 - b. The actual cost of production must be determined and not a notional lower cost of production in order to determine a price which can be compared with the import price in order to assess injury margin.
 - c. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets, or at the least gross value of fixed assets, in fact, the most appropriate value for the purpose is present value of the investments.

- v. It is submitted that price undercutting and injury margin should be calculated considering only injurious transactions i.e. considering those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the domestic industry as was determined by the petitioner. The principle is also applied in the WTO Report in the matter of European Communities - Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil.
- vi. It is submitted that the Domestic industry is suffering material injury on account of dumped imports as apparent from the disclosure issued.
- vii. Fixed form of anti dumping duty is required to be imposed for a period of five years expressed in US/MT. It is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price thus the duty should be imposed in a manner where it does not become futile.

Submissions made by the opposing interested parties

80. The submissions of various opposing interested parties are summarized as follows:

- i. It is submitted that there are serious inconsistencies in the Petition concerning excessive confidentiality and the data provided to the extent that no meaningful analysis could be carried out.
- ii. It is submitted that the Authority had calculated the normal value for Producer i.e. M/s Qatar Vinyl Company (QVC) based on the domestic sales to calculate a skewed and inflated dumping margin which is erroneous and not factual and has disregarded the request of the producer as to why domestic sales are not in the ordinary course of trade and should not be considered for determining the normal value. There are no reasons provided as to why the same has been accepted irrespective of appreciating and considering the particular market situation.
- iii. M/s Tosoh Corporation has disputed the calculation of cost of production which has led to failure in ordinary course of trade test. The Authority should re-examine the detailed cost calculations as per the details given by the producer. Further, the adjustments for calculation of Net Export Price at ex-factory level may also be re-looked and the adjustment claimed by the Exporter be accepted.
- iv. It is submitted that there is negative price underselling from Qatar, hence there cannot be price injury without price underselling. Further it is submitted that there is no dumping and injury to the Domestic Industry from the exports being made from Qatar especially the cooperating channel.
- v. It is submitted that all the exporters and the producers involved in the trade channel from Japan have duly participated and furnished all the requisite data, there is no dumping and injury from the Cooperating Exporter and producers. Therefore, the Authority is requested not to levy any duties for exports of product under consideration from the cooperative Exporter and Producers.
- vi. It is submitted that there is lack of causality in injury in terms of analysis of economic parameters during the injury period and the imports made from Japan during the same period.
- vii. The rate of 22% on return on capital employed is not based on any logical basis.

Examination by the Authority

81. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs, however for the sake of the clarity of the submissions they are addressed as below:

- i. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the justification of their claims and the specific provisions of law as interpreted by the Hon'ble Supreme Court. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality

claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

- ii. The issue of withdrawal of petition and termination of investigation has been dealt with in detail in relevant paras above.
- iii. The Authority has not relied on the information from IHS in view of the detailed information/data given by the co-operative producer/exporter and the same has been accepted after due verification.
- iv. As regards the calculation of NIP, the Authority reiterates that NIP and cost of production has been determined as per the Rules and the practices followed in the Directorate.
- v. The undercutting and underselling has been calculated based on DGCI&S data and the petitioners demand to calculate the same only on the basis of injurious transactions is not accepted.
- vi. The Authority has accepted the domestic sales of M/s Qatar Vinyl Company (QVC), as the transactions are made in the ordinary course of trade though with significant profit margins. The request of the exporter in this regard seeking rejection of their normal value is unusual and hence rejected.
- vii. The Authority has re-examined and re-calculated the cost of production of M/s Tosoh Corporation, Japan and finds that more than 80% of domestic sales transactions are profit making and hence has determined the normal value based all sales transactions.
- viii. As regards the calculation of Net Export Price of M/s Tosoh Corporation, Japan it is noted that the same have been clearly mentioned in the above relevant para that adjustment claimed by the exporter and accepted by the Authority after necessary verification of documents were on account of overseas freight, clearance & handling charges, overseas insurance, brokerage and credit expense. However, the adjustments claimed by the exporter but not accepted by the Authority were on account of surveyor cost, storage cost, handling cost, insurance cost, others and credit cost. It is on the basis of comparison of adjustments sought and accepted for other producers/exporters from Japan.
- ix. The analysis of underselling on the basis of DGCI&S data indicates that it is negative. However, the data submitted by co-operating producer/exporter from Qatar indicates a significant dumping margin but insignificant injury margin in one channel and negative injury margin in case of exports through unrelated traders.
- x. As regards the economic factors of the domestic industry, it is noted that the same has been carefully examined by the Authority in the relevant paras of the finding.

J. CONCLUSIONS

82. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration has been exported to India from Qatar at significantly dumped prices as compared to its normal value, however, the same are not causing material injury to the domestic industry.
- ii. The product under consideration has been exported to India by M/s Asahi Glass Co., Ltd Japan at prices which are at dumped prices however, the same are not causing material injury to the domestic industry.
- iii. The product under consideration has been exported to India by M/s Tosoh Corporation Japan at prices which are marginally lower than the normal value of the producer and dumping margin is below de

minimus. Further, the material injury caused to the domestic industry on account of M/s Tosoh Corporation is insignificant.

- iv. The product under consideration has been exported to India by M/s Shin-Etsu Chemical Co., Ltd Japan at prices which are marginally lower than the normal value of the producer, however, the dumping margin and injury margin are insignificant and hence could not be held responsible for causing the material injury to the domestic industry.
- v. The injury analysis indicates that the domestic industry is not suffering from injury and the alleged dumped imports from the subject countries are not resulting in material injury to the Domestic Industry.

K. RECOMMENDATION

83. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules it is established that the alleged dumped imports are not causing material injury to the Domestic Industry. The Authority is of the view that imposition of antidumping duty is not warranted in the present investigation. Therefore, the Authority considers it appropriate to recommend termination of investigation in terms of Rule 14(b) of the Rules.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority